

खैरगुड़ा में नए स्कूल भवन का लोकार्पण, छात्रा ने भी काटा जन्मदिन का केक

सरपंच ईश्वर मंडवी और भाजपा मंडल अध्यक्ष सुखदेव मंडवी तबसिंह ठाकुर की मौजूदगी में हुआ कार्यक्रम, प्रधान अध्यापक ने श्रावणी में भ्रमण की अपील



खैरगुड़ा। बस्तर विकासखंड के ग्राम पंचायत मधोला-02 अंतर्गत प्राथमिक शाला खैरगुड़ा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती और छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा-अर्चना से हुई। इसके बाद सरपंच ईश्वर मंडवी एवं तबसिंह ठाकुर ने फ़ैता काटकर नए शाला भवन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सरपंच ईश्वर मंडवी और भाजपा बस्तर मंडल अध्यक्ष सुखदेव मंडवी ने कहा कि विद्यालय विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण की आधारशिला है। नए भवन से विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक

वातावरण उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। उन्होंने शिक्षकों, पालकों और श्रावणी से

विद्यालय के विकास में सहयोग करने तथा परिसर को स्वच्छ

बनाए रखने की अपील की।

प्रधान अध्यापक ने जताया आभार

प्राथमिक शाला के प्रधान अध्यापक छत्रु राम मंडवी ने भवन के लोकार्पण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों और श्रावणी के प्रति आभार जताया। उन्होंने पालकों से विद्यालय परिसर की साफ सफ़ाई में श्रमदान करने और स्कूल को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग देने की अपील की। कार्यक्रम में भाजपा बस्तर मंडल अध्यक्ष सुखदेव मंडवी, लोकनाथ ठाकुर, बलदेव, राजपाल सिंह ठाकुर, घेनवा ठाकुर, सुखदेव ठाकुर, मुरली, त्रिनाथ, सोनसाय, संजय सिंह, नरेश, गिरिराम, मनोज कुमार, सुरेश, डमरू यादव, शिक्षिका इंदुमती एवं लिकेश कश्यप

सहित बड़ी संख्या में श्रावणीजन, महिलाएं एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।

लोकार्पण के दिन छात्रा का जन्मदिन भी

कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की एक छात्रा का जन्मदिन भी था। सरपंच ईश्वर मंडवी ने इसे सुखद संयोग बताया। भवन के लोकार्पण के बाद उसी परिसर में केक काटकर छात्रा का जन्मदिन मनाया गया। सरपंच ईश्वर मंडवी और मंडल अध्यक्ष सुखदेव मंडवी ने छात्रा को जन्मदिन की बधाई देते हुए उसके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी छात्रा को शुभकामनाएं दीं।

चित्रकला के माध्यम से छात्रों ने दिया ऊर्जा संरक्षण का संदेश



कवर्धा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के सहयोग से नेशनल पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑन एनर्जी कंजर्वेशन-2026 के अंतर्गत देश भर में चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसका मुख्य विषय ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता निर्धारित किया गया है। इसी राष्ट्रीय अभियान के क्रम में जिले के शासकीय हाई स्कूल छिह्वा में ऊर्जा संरक्षण विषय पर एक आकर्षक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें

विद्यालय के विद्यार्थियों ने बड़े उत्साह के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया। संस्था के प्राचार्य डॉ. रमेश चन्द्रवंशी ने बताया कि दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण के महत्व को जन-जन तक पहुंचाने और विद्यार्थियों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इस विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के कुल 18 छात्र-छात्राओं ने भाग लेकर अपनी रचनात्मक सोच को रंगों के माध्यम से कैमवास पर उकेरा। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने बिजली बचाने, नवीकरणीय ऊर्जा

स्रोतों के उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े सुंदर चित्र बनाए, जिसमें कक्षा दसवीं की छात्रा गुंजन दिवाकर ने अपनी उत्कृष्ट कलाकृति के बल पर प्रथम एवं रितु यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के प्राचार्य डॉ. रमेश चन्द्रवंशी, व्याख्याता रंजीता माहेधरी, कल्पना मणवी, वीणाक्षी नामदेव एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। इस दौरान विद्यार्थियों ने ऊर्जा संरक्षण का संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

दिवाकर तिवारी पुनः छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष मनोनीत



जांजगीर चांपा। छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज केंद्रीय समिति की कार्यकारिणी एवं आजीवन सदस्य की बैठक रविवार को अग्रोहा कॉलोनी स्थित वर्तमान अध्यक्ष दिवाकर तिवारी के निवास पर हुई। बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यों और संरक्षकों ने दिवाकर तिवारी को अपने कार्यकाल के लिये पुनः अध्यक्ष मनोनीत करने का

प्रस्ताव रखा। उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यों और आजीवन सदस्यों ने प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सहमति जताई। बैठक में दिवाकर तिवारी को अक्टूबर 2026 से अक्टूबर 2029 तक के कार्यकाल के लिए समिति का अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर संरक्षक छगन चौबे, प्रमोद दुबे(पूर्व महापौर), आकाश दुबे,ललित मिश्रा पूर्व अध्यक्ष सतीश

स्वर संगम सीजन-1 सम्पन्न, सभागार सुरों से गूँजा

कवर्धा। गोल्लन वॉइस इवेंट्स द्वारा आयोजित जिले का सबसे बड़ा कराओके उत्सव स्वर संगम सीजन-1 वीर सावरकर सभागार में प्रातः 11 बजे से देर रात्रि तक भव्यता से सम्पन्न हुआ, जहाँ शहर सहित लोरमी, पंडरिया, तखतपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव व दुर्ग से पहुंचे 40 से भी अधिक गायन प्रतिभाओं ने समा बांध दिया, नही अह्निका रावत ने 'मनवा लागे', प्रसिद्धि नामदेव ने गुजराती गीत, आस्था तिवारी ने क्लासिकल गीत, पंडरिया के हमीदुल्ला खान ने 'बीते हुए लम्हों की कसक', राजनांदगांव के विकास ठाकुर ने 'एक अजनबी हसीना से', लोरमी के इंद्रजीत छबड़ा ने 'मेरी उमर के नौजवानों', डॉ शैलेन्द्र प्रधान ने रंग और नूर की बारात, बिलासपुर के विकेश यादव ने 'रुके रुके से कदम' और पहली बार मंच पर आए देवेंद्र सिंह राजपुत ने 'जुबां पे दर्द भरी दास्ता' से



श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं महिला स्वरो में रीना सोनवानी, अनिता रावत, ज्योति ठाकुर, रंजना झा, उमा ठाकुर, गायत्री चंद्रवंशी, सती मरकाम, तरुणा नामदेव, नीतू भट्ट व ललित मेरावी ने तथा लोरमी अंचल से डॉ. श्रवण लांडीवार, नोहर कोहली, राम खिलानव, युगल किशोर, धर्मराज साहू व ललित साहू ने और युवा स्वरो में लेश्वर ठाकुर, कुलदीप यादव, राकेश कोल, सोनू

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के प्रभाव से जिले में बारिश की संभावना



धान सहित दलहन-तिलहन की कटाई फ़िल्हाल टालें, कटी फ़सलों को सुरक्षित स्थान पर रखें

मुंगेली, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से चक्रवाती तूफान 'अर्नब' की संभावना को देखते हुए छत्तीसगढ़ में मौसम प्रभावित होने की आशंका है। इसके प्रभाव से मुंगेली जिले में 29 अक्टूबर तक वर्षा होने की संभावना जताई गई है। इसे ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग ने जिले के किसानों को फ़सलों, सब्जियों, फलदार पौधों एवं पशुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है। तेज हवा और वर्षा की संभावना को देखते हुए खेतों में जल निकासी की व्यवस्था, कटी फ़सलों का सुरक्षित भंडारण तथा पशुओं के लिए सुरक्षित आश्रय सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। कृषि विभाग की उपसंचालक ने कहा है कि आगामी दिनों में वर्षा की संभावना को देखते हुए पकने की अवस्था में पहुंच चुकी धान, दलहन एवं तिलहन फ़सलों की कटाई अगले दो से चार दिनों तक टालने की सलाह दी गई है। जिन किसानों ने कटाई शुरू कर दी है, वे कटी हुई फ़सलों को जल्द से जल्द सुरक्षित एवं सूखे स्थान पर रखें। खेतों में अतिरिक्त पानी जमा होने से फ़सलों को नुकसान हो सकता है, इसलिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें। किसानों को खेतों की निर्यामित निगरानी करने तथा फ़सलों में कीट या रोग के लक्षण दिखाई देने

पर मौसम साफ होने के बाद आवश्यकतानुसार कीटनाशक एवं कवकनाशक का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। उतारा फ़सल के रूप में तिवारा या अलसी की बुवाई करने वाले किसान फ़िल्हाल कुछ दिनों तक बुवाई स्थगित रखें। वहीं, रबी फ़सलों की बुवाई नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ करने की सलाह दी गई है। वर्षा एवं तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए सब्जी उत्पादक किसानों को भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। फूलगोभी, ब्रोकली, चुकंदर, पखैली खीरा और पखैली करेला जैसी रबी सब्जियों की बुवाई नवंबर माह के प्रथम सप्ताह से शुरू करने को कहा गया है। लौकी, करेला सहित अन्य सब्जियों को तेज हवाओं से बचाने के लिए उचित सहारा देने की व्यवस्था करें। जिन केले के पौधों में फूल या फल आ चुके हैं, उन्हें बांस अथवा अन्य उपयुक्त साधनों से सहारा दें, ताकि तेज हवा से पौधों के गिरने या टूटने की आशंका कम हो सके। भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए सब्जियों एवं बागवानी फ़सलों के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा खेतों की निर्यामित निगरानी करने की सलाह दी गई है। जहाँ उपलब्ध हो, वहाँ ओलावृष्टि से बचाव के लिए उपयुक्त जाली का उपयोग भी किया जा सकता है। वर्षा की संभावना को देखते हुए पशुओं को सूखे एवं सुरक्षित स्थान पर रखें तथा उनके लिए पर्याप्त चारा और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वज्रपात की आशंका के दौरान पशुओं को चराने से बचें और किसी भी स्थिति में पेड़ों के नीचे आश्रय न लें।

सतत आंतरिक मूल्यांकन को रद्द कर, युवा महोत्सव की तैयारी, बच्चों में नाराजगी



मोहला। शासकीय नवीन महाविद्यालय मोहला में आयोजित किए जा रहे युवा महोत्सव के कारण सतत आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा को रद्द किए जाने का मामला विद्यार्थियों के बीच नाराजगी का विषय बना हुआ है। सतत आंतरिक मूल्यांकन को रद्द करके युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। विद्यार्थियों की इस नाराजगी और उनकी शैक्षणिक

चिंताओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विधायक मंडवी ने छात्रों की बात को ध्यान में रखते हुए, मोहला में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि सतत आंतरिक मूल्यांकन विद्यार्थियों की पढ़ाई और शैक्षणिक प्रगति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। परीक्षा को रद्द करने से विद्यार्थियों की पढ़ाई की समय-सारणी प्रभावित हुई है और उनके मन में असमंजस की स्थिति पैदा

ग्राम लब्दा में कोदो प्रसंस्करण गतिविधि का शैक्षणिक भ्रमण, 31 प्रतिभागियों ने लिया भाग



कवर्धा। शिखर युवा मंच एवं सीएएमएस फंडेशन के सहयोग से कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड अंतर्गत ग्राम लब्दा में मां सरस्वती स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित कोदो प्रसंस्करण गतिविधि का अवलोकन करने के लिए निर्माण संस्था, जिला मण्डला मध्यप्रदेश के प्रतिनिधियों एवं समूह के महिलाओं ने शैक्षणिक भ्रमण किया। इसमें कुल 31 प्रतिभागी शामिल थे जिसमें 25 महिलाएं एवं 6 पुरुषों ने भाग लिया। भ्रमण के दौरान मां सरस्वती समूह की महिलाओं ने कोदो की खेरीदी, साफ सफ़ाई, दराई, पैकेजिंग एवं

विपणन की प्रक्रिया के साथ लागत, बिक्री, लाभ और दस्तावेज संधारण की जानकारी साझा की। प्रतिभागियों ने कोदो की दराई प्रक्रिया का व्यावहारिक अध्ययन भी किया तथा समूह के अनुभवों को साझा। इस अवसर पर समूह से 20 किलोग्राम कोदो का क्रय भी किया गया, जिससे स्थानीय उत्पाद की बिक्री को प्रोत्साहन मिला। यह शैक्षणिक भ्रमण महिला समूहों की आजीविका को मजबूत करने तथा मोटे अनाज आधारित गतिविधियों के अनुभवों के आदान-प्रदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रही। शिखर युवा मंच

के संस्था प्रमुख भूपेश वैष्णव ने कहा कि मां सरस्वती स्वयं सहायता समूह, ग्राम लब्दा की महिलाओं को कोदो प्रसंस्करण एवं विपणन गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा उद्देश्य महिलाओं की क्षमता को विकसित करना, उनके उत्पादों के विपणन के अवसर बढ़ाना तथा उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम में शिखर युवा मंच की ओर से अयोध्या जायसवाल, संतोष साकत, विष्णु मेरावी, श्रीमती कमलेश्वर मरकोले एवं श्रीमती नंदनी मरकाम उपस्थित रहे।

सुकमा में टीबी उन्मूलन को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित

सुकमा। लेफ़ा सोसाइटी के टीबी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, सुकमा के सभाकक्ष में टीबी कार्यक्रम को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य टीबी के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, संभावित मरीजों की शीघ्र पहचान, समय पर जाँच एवं उपचार सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। बैठक में एड्डा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला क्षय अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारी, DPPM सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, NTEP टीम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी एवं मितानिन प्रशिक्षकों ने सहभागिता की। कार्यक्रम के दौरान डॉ. प्रवीण तेली जी ने प्रस्तुति के माध्यम से टीबी के लक्षणों, जाँच, उपचार तथा संभावित मरीजों की पहचान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके पश्चात CMHO, DPM, DTO



DPPM सहित उपस्थित अधिकारियों ने टीबी उन्मूलन के प्रभावी क्रियान्वयन, मैदानी स्तर पर गतिविधियों को मजबूत करने तथा स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर समन्वय स्थापित करने के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार एवं सुझाव प्रस्तुत किए। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभागीय समन्वय, सामुदायिक सहभागिता, समय पर मरीजों की पहचान, गुणवत्तापूर्ण जाँच एवं उपचार की निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य

विभाग, NTEP टीम, CHO एवं मितानिनों की सक्रिय भागीदारी से टीबी नियंत्रण गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। लेफ़ा सोसाइटी के जिला परियोजना समन्वयक यशपाल जायसवाल ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों, स्वास्थ्यकर्मियों, NTEP टीम एवं मितानिन प्रशिक्षकों से अपील की है। उन्होंने टीबी उन्मूलन के साझा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी से आपसी समन्वय, जन-जागरूकता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपील की।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कथित अमर्यादित बयानबाजी पर रियाजुद्दीन राजू कुरैशी ने जताई आपत्ति

कहा—राजनीतिक मतभेदों के बीच भाषा की मर्यादा और लोकतांत्रिक गरिमा बनाए रखना जरूरी

अंबागढ़ चौकी। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कथित अमर्यादित बयानबाजी को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी रियाजुद्दीन (राजू) कुरैशी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर आसीन प्रधानमंत्री के प्रति सार्वजनिक संवाद में मर्यादा और शालीनता बनाए रखना लोकतांत्रिक परंपराओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रियाजुद्दीन राजू कुरैशी ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की नीतियों और निर्णयों की आलोचना करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन राजनीतिक असहमति व्यक्त करते समय भाषा की गरिमा बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बीच विचारों का मतभेद स्वाभाविक है, मगर सार्वजनिक जीवन में संवाद ऐसा होना चाहिए, जिससे लोकतांत्रिक



संस्थाओं और राजनीतिक विमर्श की गरिमा बनी रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नीतियों और योजनाओं

सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से राजनीतिक संवाद में शालीनता और मर्यादा बनाए रखने की अपील की।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा प्रदेश मीडिया विभाग की बैठक में सरकार की उपलब्धियां जन-जन तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया विभाग की आवश्यक बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आयोजित की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों, मीडिया प्रबंधन और केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा हुई। शुरुआत में प्रदेश प्रवक्ताओं ने अपना परिचय दिया। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि मीडिया विभाग पार्टी की विचारधारा और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने पदाधिकारियों से तथ्यों के आधार पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने और सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाने का आह्वान किया। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता एवं संसद संतोष पांडेय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना मीडिया विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों और दुष्प्रचार का तथ्यपरक जवाब देने पर भी जोर दिया। बैठक का संचालन प्रदेश मीडिया संयोजक हेमंत पाणिग्रही ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन प्रदेश प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती ने किया। इस अवसर पर प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी, प्रदेश प्रवक्तागण और मीडिया विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

एसी का आउटडोर चोरी कर बेचने वाला आरोपी और दो खरीदार गिरफ्तार

रयपुर। शहर में शोरूम के सामने से एसी का आउटडोर चोरी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी और चोरी का सामान खरीदने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया एसी आउटडोर, नकद रकम और एक मोबाइल फोन जब्त किया है। तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार, भदरापारा बाल्को के नगर निवासी प्रमोद कुमार यादव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 अक्टूबर 2026 को हुंडई शोल्म पहूंचने पर सामने लगा एसी का आउटडोर गायब मिला। शिकायत के आधार पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 877/2026 के तहत धारा 303(2), 317(2) और 3(5) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने गुड्डू बरेठ (23), निवासी शीतला मंदिर के पास, मोतीसागरपारा से पृष्ठताछ की। पुलिस के मुताबिक, उसने एसी का आउटडोर चोरी कर कृष्णा बसोड़ (22), निवासी बसोड़ मोहल्ल, इमलीडुगू को बेचने की बात स्वीकार की।

शिवम सिटी सड्डू में 75 लाख रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन

रायपुर। रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू ने नगर निगम जोन-9 के अंतर्गत महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 8 स्थित शिवम सिटी सड्डू में लगभग 75 लाख रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इन कार्यों में नई सीसी रोड और नाली निर्माण शामिल हैं, जिससे क्षेत्र में आवागमन और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर बनाने का लक्ष्य है। भूमिपूजन के दौरान विधायक ने शिवम सिटी सड्डू में 40 लाख रुपये की लागत से सिटी रोड निर्माण तथा 25 लाख रुपये की लागत से नालियों के निर्माण कार्य की शुरुआत के लिए भूमिपूजन किया। इसके अलावा शिवम सिटी सेक्टर-3 में गंदे पानी की सुगम निकासी के लिए 9.85 लाख रुपये की लागत से नई नालियों का निर्माण कराया जाएगा। विधायक मोतीलाल साहू ने नगर निगम के जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव और कार्यपालन अभियंता शरद ध्वव को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य जल्द शुरू कराए जाएं। उन्होंने कार्यों की नियमित निगरानी करने और तय समयसीमा में गुणवत्ता के साथ निर्माण पूरा कराने पर जोर दिया।

छत्तीसगढ़ में गांजा तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा, 7 आरोपी गिरफ्तार; 25.41 लाख का माल जब्त

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन निष्पत्य के तहत सिमगा पुलिस ने महासमुंद और बिलासपुर पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ओडिशा से गांजे की खेप लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जा रहे थे। उनके कब्जे से गांजा, दो कार और मोबाइल फोन समेत कुल 25 लाख 41 हजार 500 रुपये की सामग्री जब्त की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर को सिमगा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सफेद स्विफ्ट कार में गांजा भरकर ओडिशा से उत्तर प्रदेश ले जाया जा रहा है। तस्करी में शामिल गिरोह पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्विफ्ट कार से आगे बलेंगे कार चला रहा था, ताकि रास्ते में पुलिस की चेकिंग को जानकारी मिल सके। सूचना के आधार पर पुलिस ने सिमगा ओवरब्रिज और राष्ट्रीय राजमार्ग-130 पर नाकेबंदी की।

आईटीएम विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में नवाचार

उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर राज्यपाल ने दिया जोर

■ लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम, अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलें

रायपुर/ संवाददाता

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने युवाओं से अपने नए विचारों को स्टार्टअप में बदलने, नवाचार को अपनाने और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है और युवाओं के विचार देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे सकते हैं। स्टार्टअप की संभावनाएं अब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि छोटे शहरों और गांवों में भी नए उद्यम आकार ले रहे हैं। युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी पहचान

रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत छूट से महिलाओं को मिल रही बड़ी राहत....

■ प्लॉट की रजिस्ट्री में मनोरमा बैद्य और रितु जैन को लगभग 2 लाख 90 हजार 700 रुपये की बचत

रायपुर। संवाददाता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। महिलाओं के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री कराने पर पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट देने का राज्य शासन का निर्णय महिलाओं और उनके परिवारों के लिए बड़ी आर्थिक राहत साबित हो रहा है। इस पहल से महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने को प्रोत्साहन मिल रहा है, वहीं संपत्ति में उनका स्वाभिवू और परिवार की आर्थिक सुरक्षा भी मजबूत हो रही है। राज्य शासन की इस जनहितैषी पहल का लाभ रायपुर में मनोरमा बैद्य एवं रितु जैन को भी मिला है।

रायपुर में यातायात पुलिस के 13 अधिकारी-कर्मचारी सम्मानित.....

■ 28 किलो गांजा और चोरी के वाहन पकड़ने में निभाई अहम भूमिका

रायपुर/ संवाददाता

यातायात व्यवस्था सुचारु बनाने के साथ अपराध नियंत्रण और चोरी के मामलों में उल्लेखनीय कार्रवाई करने वाले यातायात पुलिस के 13 अधिकारी-कर्मचारियों को पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इन पुलिसकर्मियों ने एक सप्ताह के भीतर छह अलग-अलग मामलों में सक्रियता दिखाते हुए मादक पदार्थों की जब्त, चोरी के वाहनों की

स्वयं बनानी चाहिए। राज्यपाल श्री रमेन डेका आज आईटीएम विश्वविद्यालय, रायपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 16 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक, चार शोधार्थियों को पीएचडी तथा 464 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधियां प्रदान की गईं। राज्यपाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप और उद्यमिता के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। युवा अपने विचारों को व्यावहारिक रूप देकर नए उद्यम शुरू कर सकते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे केवल नौकरी पाने तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी क्षमता, ज्ञान और रचनात्मकता के बल पर रोजगार सृजन की दिशा में भी आगे बढ़ें। अपने आइडिया को स्टार्टअप में बदलें, अपनी जगह स्वयं बनाएं और सफलता के बाद

उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर 2026 को रायपुर स्थित पंजीयन कार्यालय में उनके नाम पर प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई। महिलाओं के लिए लागू 50 प्रतिशत पंजीयन शुल्क छूट का लाभ मिलने से उन्हें लगभग 2 लाख 90 हजार 700 रुपये की बचत हुई। इतनी बड़ी राशि की बचत होने से उनके परिवार को आर्थिक राहत मिली है और संपत्ति खरीदने की खुशी भी दुोगुनी हो गई। मनोरमा बैद्य एवं रितु जैन ने बताया कि वे लंबे समय से अपने परिवार के सुरक्षित भविष्य के लिए संपत्ति में निवेश करने की योजना बना रही थीं। रायपुर में प्लॉट खरीदना उनके परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय था, लेकिन संपत्ति की रजिस्ट्री पर होने वाला अतिरिक्त खर्च चिंता का विषय बना हुआ था। ऐसे समय में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री में दी जा रही 50 प्रतिशत छूट उनके लिए बड़ी राहत बनकर सामने आई। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्री शुल्क में छूट से बची राशि का उपयोग अब परिवार को अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए किया जा सकेगा।

मनियाारी नदी और डोंगानाला पर बनेंगे उच्च स्तरीय पुल, 14.26 करोड़ रुपये मंजूर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली और बिलासपुर जिले में सड़क संपर्क और आवागमन को बेहतर बनाने के लिए मनियाारी नदी और डोंगानाला पर दो उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद लोक निर्माण विभाग ने दोनों पुलों और उनके पहुंच मार्गों के निर्माण के लिए कुल 14 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की है। मुंगेली जिले के तखतपुर-बरेला राज्य मार्ग पर मनियाारी नदी में मौजूदा जलमग्नोय पुल के स्थान पर नया उच्च स्तरीय पुल बनाया जाएगा। इसके निर्माण और पहुंच मार्ग के लिए 7 करोड़ 67 लाख 11 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वर्तमान में नदी का जलस्तर बढ़ने पर इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका रहती है।

प्रोजेक्ट धड़कन से बच्चों को मिल रहा नया जीवन, 29 का हुआ निःशुल्क हृदय आपरेशन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार रायपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट धड़कन जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीद बन रहा है। इस अभिनव पहल के अंतर्गत जिले में अब तक 2 लाख 58 हजार 838 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। वहीं 29 बच्चों के हृदय का निःशुल्क आपरेशन कराया गया है तथा 9 बच्चों को आवश्यक चिकित्सा उपचार एवं प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल से बच्चों को स्वस्थ जीवन की नई उम्मीद मिली है और उनके माता-पिता के चेहरों पर खुशियां लौटी हैं। कलेक्टर डा. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन एवं सत्य साई अस्पताल के सहयोग से जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में बच्चों को प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर हृदय रोग के संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर उन्हें विस्तृत जांच के लिए चिह्नंकित किया जाता है। बीमारी की पुष्टि होने पर बच्चों को आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपचार एवं आपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रोजेक्ट धड़कन का उद्देश्य जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर बच्चों को समुचित उपचार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में संचालित यह पहल ज़रूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत प्रदान कर रही है।

संभावित चक्रवात अर्नब का खतरा-छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी

कलेक्टरों को 27 से 29 अक्टूबर तक विशेष एहतियात बरतने के लिए निर्देश-अपर मुख्य सचिव पिंगुआ.....

रायपुर/ संवाददाता

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफ़ान 'अर्नब' का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ने की संभावनाओं के मद्देनजर शासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। इसे लेकर पंजालय महानदी भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चक्रवात के मद्देनजर 27 से 29 अक्टूबर तक आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े। अपर मुख्य सचिव ने

अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए और मौसम संबंधी चेतावनियों को पूरी गंभीरता से लिया जाए। बैठक में मुख्य जोर शून्य जनहानि सुनिश्चित करने पर रहा। इसके तहत विशेष रूप से दक्षिण बस्तर क्षेत्र के बीजापुर, सुकमा, दंतवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों में अत्यधिक सर्तकता बरतने के निर्देश दिए



समाज को न भूलें। उन्होंने कहा कि समाज ने प्रत्येक व्यक्ति को बहुत कुछ दिया है, इसलिए समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि दीक्षांत समारोह विद्यार्थियों के जीवन की एक पारी के समापन और दूसरी पारी की शुरुआत का प्रतीक है। आगे का जीवन चुनौतियों और संघर्षों से भरा हो सकता है, लेकिन मेहनत, धैर्य और

आत्मविश्वास से उनका सामना किया जा सकता है। विद्यार्थियों को अपनी रुचि के क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए, जिससे उन्हें संतुष्टि मिले और वे सफलता हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि डिग्री केवल एक प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि अर्जित ज्ञान और कौशल के माध्यम से परिवार, समाज और देश के प्रति दायित्व निभाने का अवसर है। शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना

एसआईआर के दौरान फार्म-7 के दुरुपयोग का आरोप

अकबर ने उठाए सवाल करीब 25 लाख मतदाताओं के नाम काटे.....

रायपुर। संवाददाता

पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने प्रदेश की मतदाता सूची में लगभग 25 लाख मतदाताओं के नाम कम होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फॉर्म-7 के जरिए मतदाताओं के नाम काटे जाने की पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की है। दस्तावेजों के आधार पर जारी बयान में मोहम्मद अकबर ने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक प्रदेश की आबादी बढ़ी है, लेकिन मतदाताओं की संख्या में 24 लाख 99 हजार की कमी आई है। भारत निर्वाचन आयोग को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़े

महतारी वंदन की बचत से दीपिका ने शुरू किया सिलाई का काम

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार रायपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित प्रोजेक्ट धड़कन जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीद बन रहा है। इस अभिनव पहल के अंतर्गत जिले में अब तक 2 लाख 58 हजार 838 बच्चों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। वहीं 29 बच्चों के हृदय का निःशुल्क आपरेशन कराया गया है तथा 9 बच्चों को आवश्यक चिकित्सा उपचार एवं प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस पहल से बच्चों को स्वस्थ जीवन की नई उम्मीद मिली है और उनके माता-पिता के चेहरों पर खुशियां लौटी हैं। कलेक्टर डा. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन एवं सत्य साई अस्पताल के सहयोग से जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में बच्चों को प्रारंभिक स्क्रीनिंग कर हृदय रोग के संदिग्ध लक्षण पाए जाने पर उन्हें विस्तृत जांच के लिए चिह्नंकित किया जाता है। बीमारी की पुष्टि होने पर बच्चों को आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपचार एवं आपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रोजेक्ट धड़कन का उद्देश्य जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर बच्चों को समुचित उपचार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में संचालित यह पहल ज़रूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत प्रदान कर रही है।

संभावित चक्रवात अर्नब का खतरा-छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जारी

कलेक्टरों को 27 से 29 अक्टूबर तक विशेष एहतियात बरतने के लिए निर्देश-अपर मुख्य सचिव पिंगुआ.....

रायपुर/ संवाददाता

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफ़ान 'अर्नब' का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ने की संभावनाओं के मद्देनजर शासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। इसे लेकर पंजालय महानदी भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चक्रवात के मद्देनजर 27 से 29 अक्टूबर तक आवश्यक तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी जुड़े। अपर मुख्य सचिव ने

अधिकारियों को निर्देश दिया है कि चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखी जाए और मौसम संबंधी चेतावनियों को पूरी गंभीरता से लिया जाए। बैठक में मुख्य जोर शून्य जनहानि सुनिश्चित करने पर रहा। इसके तहत विशेष रूप से दक्षिण बस्तर क्षेत्र के बीजापुर, सुकमा, दंतवाड़ा, बस्तर और नारायणपुर जिलों में अत्यधिक सर्तकता बरतने के निर्देश दिए

नहीं, बल्कि सही-गलत का विवेक विकसित करना और जिम्मेदार नागरिक बनाना भी है। युवाओं को डिग्री को अंतिम मंजिल नहीं मानना चाहिए, बल्कि निरंतर सीखने और नए प्रयोग करने की प्रवृत्ति बनाए रखनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शांति और सुरक्षा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मोबाइल के युग में आगे बढ़ रहे हैं। इन तकनीकों के पीछे भी मानवीय बुद्धि का योगदान है। उन्होंने डिजिटल लत और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति से युवाओं को दूर रहने की सलाह दी। ज़रूरत के अनुसार ही मोबाइल का उपयोग करने तथा परिवार, मित्रों और समाज के साथ संवाद बनाए रखने पर जोर दिया। राज्यपाल ने कहा कि शांति और सुरक्षा से विकास की गति मिलती है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के प्रभाव में कमी के बाद बने विकास के अवसरों तथा बस्तर में आजीविका के क्षेत्र में हो

एसआईआर के दौरान फार्म-7 के दुरुपयोग का आरोप

अकबर ने उठाए सवाल करीब 25 लाख मतदाताओं के नाम काटे.....

रायपुर। संवाददाता

पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने प्रदेश की मतदाता सूची में लगभग 25 लाख मतदाताओं के नाम कम होने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फॉर्म-7 के जरिए मतदाताओं के नाम काटे जाने की पूरी प्रक्रिया की जांच की मांग की है। दस्तावेजों के आधार पर जारी बयान में मोहम्मद अकबर ने कहा कि वर्ष 2023 से अब तक प्रदेश की आबादी बढ़ी है, लेकिन मतदाताओं की संख्या में 24 लाख 99 हजार की कमी आई है। भारत निर्वाचन आयोग को इस मामले में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़े

पैमाने पर फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर मतदाताओं के नाम कटवाए गए हैं। इस दौरान निर्धारित प्रक्रियाओं और नियमों का पालन नहीं किए जाने को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रावधानों के अनुसार, फॉर्म-7 के माध्यम से दर्ज आपत्ति पर सुनवाई के दौरान सबसे पहले आपत्तिकर्ता को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप

महतारी वंदन की बचत से दीपिका ने शुरू किया सिलाई का काम



■ घर बैठे हो रही अतिरिक्त आमदनी से बच्चों की पढ़ाई और घरेलू खर्च में कर रही सहयोग

रायपुर/ संवाददाता

सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के ग्राम केवरी की श्रीमती दीपिका दास ने महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि को बचाकर अपने हुनर को आजीविका का साधन बनाया है। उन्होंने इसी बचत से सिलाई का काम शुरू किया। अब गांव की महिलाओं के कपड़े सिलकर वे हर महीने अतिरिक्त आमदनी अर्जित कर रही हैं और परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियों में हाथ बंट्य रही हैं। श्रीमती दीपिका बताती हैं कि पहले सीमित संसाधनों के कारण घर की जरूरतें पूरी करने और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में परेशानी होती थी। वे भी परिवार की आय बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहती थीं। महतारी वंदन योजना से नियमित सहायता मिलने पर उन्होंने राशि का कुछ हिस्सा बचाना शुरू किया और सिलाई का काम शुरू करने का निर्णय

रहे प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन स्थलों के विकास की आवश्यकता भी बताई। अपने संबोधन में राज्यपाल ने युवाओं से बड़े सपने देखने, उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने और असफलताओं से निराश हुए बिना नए प्रयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के निर्माण में सभी का योगदान आवश्यक है। युवाओं को अपनी तरकीब के साथ समाज के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए अपने ज्ञान और हुनर का उपयोग राष्ट्र के समग्र विकास के लिए करना चाहिए। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. रामचंद्र जहांगीर ने स्वागत भाषण दिया। छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री वी.के. गोयल ने भी संबोधित किया।

से सुना जाएगा और उसका बयान दर्ज किया जाएगा। संबंधित अधिकारी को आपत्ति और उसकी वैधता के संबंध में स्वयं संतुष्ट होना होगा। इसके अलावा, जिस मतदाता के नाम पर आपत्ति दर्ज की गई है, उसे भी आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल फॉर्म-7 दाखिल कर देने से किसी मतदाता का नाम अपने आप मतदाता सूची से नहीं कट जाता। यदि कोई आवेदक फॉर्म-7 में जानबूझकर गलत जानकारी या झूठी घोषणा करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसी कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के प्रावधानों के तहत की जा सकती है।

महतारी वंदन की बचत से दीपिका ने शुरू किया सिलाई का काम



लिया। अब वे घर से ही गांव की महिलाओं के कपड़े सिलती हैं। घर पर काम करने से उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों के साथ रोजगार करने की सुविधा मिली है। सिलाई से होने वाली कमाई से बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च में सहयोग मिलता है। इस काम ने उन्हें अपनी मेहनत से आय अर्जित करने का अवसर दिया है। अपनी खुशी साझा करते हुए श्रीमती दीपिका ने कहा,पहले मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। महतारी वंदन योजना की राशि जोड़कर मैंने सिलाई का काम शुरू किया। अब घर बैठे गांव की महिलाओं के कपड़े सिलती हूं। इससे बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च में मदद मिलती है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताते हुए कहा कि विष्णु भैया की पहल से उन्हें रोजगार शुरू करने का संबल मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और महिला एवं बाल विकास मंत्री के मार्गदर्शन में संचालित महतारी वंदन योजना महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ अपने जीवन और परिवार के लिए निर्णय लेने का भरोसा दे रही है। योजना से मिली राशि का उपयोग महिलाएं घरेलू जरूरतों, बच्चों की शिक्षा और छोटे स्वरोजगार में कर रही हैं।



संपादकीय

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए खुदरा महंगाई की दर अगस्त में क्रमशः 5.23 फीसद और 4.31 फीसद दर्ज की गई। खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति सुचारु रखने, जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रभावी निगरान करने तथा किसानों को उचित उत्पादन और भंडारण सुविधाएं देने की जरूरत है। जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार बढ़ती

हैं, तो इसका सबसे ज्यादा असर समाज के उस वर्ग पर पड़ता है, जिसकी आय कम होती है और संसाधनों का दायरा भी सीमित होता है। भोजन, कपड़े, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन जैसी आवश्यकताओं पर बढ़ता खर्च इन परिवारों के बजट को विगाड़ देता है। सरकार की ओर से बीते सोमवार को जारी महंगाई के आंकड़ों से साफ है कि आम लोगों को अब रोजमर्रा की जरूरी वस्तुओं के लिए अपनी जेब

महंगाई की दोहरी मार,आम आदमी की जेब पर बढ़ा बोझ

और ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है।खाद्य, ईंधन एवं विनिर्मित वस्तुओं के दाम बढ़ने से अगस्त में थोक महंगाई बढ़कर 9.92 फीसद, जबकि खुदरा महंगाई 4.82 फीसद पर पहुंच गई है। इससे पिछले माह जुलाई में यह क्रमशः 9.78 फीसद और 4.45 फीसद थी। जनवरी से लागू 2024 आभार वर्ष वाली नई श्रृंखला के बाद से अगस्त की खुदरा महंगाई का यह आंकड़ा अब तक का सबसे अधिक है। यही नहीं,अक्टूबर

माह से यूपीआइ के जरिए दो हजार रुपए से अधिक की राशि के भुगतान पर भी शुल्क लगाने पर सरकार की ओर से तय की गई शुल्क दरों में हालांकि आम लोगों के बीच यूपीआइ से लेन-देन को इससे बाहर रखा गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए खुदरा महंगाई की दर अगस्त में क्रमशः 5.23 फीसद और 4.31 फीसद दर्ज की गई। इससे

स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वस्तुओं के दाम ज्यादा बढ़े हैं, जहां लोगों की आय सीमित होती है। प्याज की महंगाई दर का जुलाई के 22.54 फीसद की तुलना में अगस्त में उछलकर 48.27 फीसद पर पहुंचना दर्शाता है कि प्याज आम लोगों की रसोई से गायब होने लगा है।यही हाल लहसुन और अदरक का भी है। ऐसे में निम्न और मध्य वर्गीय परिवारों को अपनी जरूरतों में कटौती करनी पड़ रही है। आय में

वृद्धि अगर महंगाई की गति से कम हो, तो घरेलू बजट को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसमें दोराय नहीं कि अगले माह की शुरुआत में जब भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक होगी, तब नीतिगत व्याज दरों पर फैसला करने में महंगाई का यह बढ़ा हुआ स्तर एक प्रमुख कारक साबित हो सकता है।यह भी महत्वपूर्ण है कि महंगाई का असर केवल घरेलू बजट तक सीमित नहीं रहता।

6 अमेरिकी सांसदों ने थामी भारत विरोधी अभियान की कमान

(नीरज कुमार दुबे)

सवाल उठता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक से समझे बिना विदेशी दबाव बनाने की यह राजनीति आखिर क्यों चल रही है? क्या किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन के आंदोलन के दौरान लगाये गये आरोपों को ही सच मानकर भारत को कटथरे में खड़ा कर देना इन सांसदों का नया शगल बन गया है?

भारत के अंदरूनी मामलों में टांग अड़ाने और दुनिया भर में भारत को कटथरे में खड़ा करने का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल, इल्हान उमर, जिम मैकगवर्न, रशीदा तलाइब, एलेनॉर होम्स नॉर्टन और जॉसस गार्सिया ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वे भारत दौरे पर छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई और कथित हिरासतों का मुद्दा उठाएं। यहां सवाल उठता है कि भारत को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने निकले इन सांसदों की आखिर किसने हक दिया कि वे हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल दें? भारत की समस्याओं पर इतनी चिंता दिखाने वाले इन नेताओं से यह भी पूछा जाना चाहिए कि उनकी यह चिंता चुनिंदा मुद्दों पर ही क्यों जागती है और भारत के मामले में वे हर बार उंगली उठाने के लिए सबसे आगे क्यों खड़े नजर आते हैं? साथ ही सवाल यह भी उठता है कि भारत जैसे विशाल लोकतंत्र पर उंगली उठाने वाले इन जनप्रतिनिधियों की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं और अंतरराष्ट्रीय आचरण की पड़ताल कौन करेगा?

वैसे यह कोई पहला अवसर नहीं है जब इन अमेरिकी नेताओं ने भारत की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। प्रमिला जयपाल ने 2019 में भी जम्मू-कश्मीर में संचार प्रतिबंधों और हिरासतों को लेकर भारत से जवाब मांगा था। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने उस समय उनके आकलन को अनुचित बताते हुए उनसे मुलाकात करने तक में रुचि नहीं दिखाई थी। अप्रैल 2022 में इल्हान उमर के पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के दौरे पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई थी और इसे देश की संप्रभुता से जुड़ा मामला बताया था। इल्हान उमर का तो अक्सर भारत विरोधी रवैया सामने आता ही रहता है।

सवाल उठता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक से समझे बिना विदेशी दबाव बनाने की यह राजनीति आखिर क्यों चल रही है? क्या किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन के आंदोलन के दौरान लगाये गये आरोपों को ही सच मानकर भारत को कटथरे में खड़ा कर देना इन सांसदों का नया शगल बन गया है? अगर इन्हें वाकई लोकतंत्र और नागरिकों की आजादी की इतनी चिंता है, तो यह चिंता हर देश के मामले में एक जैसी क्यों नहीं दिखती? आखिर भारत के मामले में ही इनका लोकतांत्रिक प्रेम क्यों उमड़ने लगता है? क्या भारत को नसीहत देना और उसके आंतरिक मामलों में दखल देना ही इनकी राजनीति का असली मकसद है?

अब बात धरव राठी की। जर्मनी में रहने वाले इस यूट्यूबर ने लंदन पहुंचकर पार्लियामेंट चौक में महात्मा गांधी की प्रतिमा के निकट 18 अक्टूबर को प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। उन्होंने भारत में कथित 'बोट चोरी' के मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की बात कही है और विदेशों में लोगों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। यहां सवाल उठता है कि अगर धरव राठी के पास वोट चोरी के सबूत थे तो वह उन्होंने अपने भारत दौरे के दौरान पुलिस या कोर्ट को क्यों नहीं दिये? क्यों वह व्यापक विदेश भाग गये? हर बात पर विदेशों में ट्विडोरा पीटना और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की चुनावी व्यवस्था को बदनाम करने की कोशिश करना आखिर किस बात का संकेत है? चुनावी प्रक्रिया से शिकायत होना अलग बात है, लेकिन अपनी राजनीतिक खुन्नस निकालने के लिए पूरी चुनाव व्यवस्था पर सवाल उठाना और दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र की साख पर बड़ा लगाने की कोशिश करना अलग बात है। देखा जाये तो आरोप लगाणा आसान है, लेकिन आरोपों को सबूतों के दम पर साबित करना ही असली कसौटी है!



सवाल यह भी है कि धरव राठी आखिर विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ इतना बड़ा अभियान किसके दम पर चला रहे हैं? लंदन में प्रदर्शन, विदेशी मंचों पर भारत को घेरने की कोशिश और देश की राजनीति को अंतरराष्ट्रीय मुद्दे बनाने की मुहिम, क्या यह सब महज संयोग है, या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? विदेशी फंडिंग के आरोपों को झुठलाने वाले धरव राठी को बताना चाहिए कि इस पूरे अभियान का पैसा कहाँ से आ रहा है, इसे कौन चला रहा है और इसके पीछे किसके हित जुड़े हैं? आखिर कौन है जो भारत की छवि को विदेशों में नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे अभियानों को ताकत दे रहा है?

साथ ही लंदन में भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में भारतीयों का मैदान उन लोगों के लिए कराया जवाब है, जो विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों कोई उनके इशारे पर चलने वाली भीड़ नहीं है। इस देश से प्यार करने वाले लाखों भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में हों, तिरंगा उठाना और अपनी सरकार के समर्थन में आवाज बुलंद करना जानते हैं। भारत के खिलाफ नारे लगाने वाले ही लोकतंत्र के ठेकेदार नहीं हैं; भारत के समर्थन में खड़े होने वालों को भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। करोड़ों भारतीयों के वोट से बनी सरकार का फैसला विदेशों में बैठे कुछ लोगों के शोर-शराबे से नहीं बदला जा सकता। भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह फैसला भारत की जनता करेगी, कोई विदेशी ताकत नहीं!

इसके अलावा, यह भी बड़ी हेरान की बात है कि संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं को भारत के मामलों में दखल देने की इतनी जल्दी रहती है कि वे किसी भी आरोप पर चिंता जताने से पहले पूरी सच्चाई जानने की जहमत तक नहीं उठाती! 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रदर्शनों के दौरान हिरासतों की खबरों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने चिंता जताई, तो भारत ने भी साफ-साफ जवाब दे दिया कि देश के आंतरिक मामलों में इस तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति में भी भारत ने इन टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताते हुए अपने सविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और स्वतंत्र प्रेस का हवाला दिया। सवाल यह है कि मानवाधिकारों की दुहाई देने वाली इन वैश्विक संस्थाओं को दुनिया के हर मामले में एक जैसी तत्परता क्यों नहीं दिखती? भारत के मामले में बिना पूरी तस्वीर

समझे बयान देने की जल्दी और दूसरे मामलों में चुप्पी...आखिर यह दोहरा रवैया कब तक चलेगा? जब संस्थाएं चुनिंदा मुद्दों पर ही जागेगी और अलग-अलग देशों के लिए अलग-अलग तराजू रखेगी, तो उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे ही। यही रवैया उनकी विश्वसनीयता को कमजोर करता है और दुनिया भर में लोगों के मन में यह सवाल खड़ा करता है कि क्या ये संस्थाएं सचमुच मानवाधिकारों की रक्षा कर रही हैं या चुनिंदा राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का जरिया बनती जा रही हैं? उधर, भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत के सविधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थाओं पर बिना पूरी जानकारी के उंगली उठाने वालों को मुहताब्द जवाब दिया जाएगा। भारत कोई ऐसा देश नहीं है कि कोई भी विदेशी संस्था या नेता उसे और बिना सोचे-समझे हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लगे! भारत के अपने कानून हैं, अपनी अदालतें हैं और अपना संवैधानिक ढांचा है। लिहाजा, भारत पर सवाल उठाने वालों को पहले तथ्यों की जांच करनी चाहिए, फिर बयानबाजी करनी चाहिए। भारत को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को यह समझना होगा कि हर आरोप पर जवाब मिलेगा और तथ्यों के दम पर मिलेगा।बहरहाल, जो लोग सत्ता पलटने का खवाब देख रहे हैं उन्हें भी समझना होगा कि भारत की ताकत किसी एक सरकार में नहीं, बल्कि उस करोड़ों भारतीयों के जनदेश में है, जिसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव मजबूत की है। इस देश को न विदेशी मंचों पर बैठकर भाषण देने वाले कुछ नेता चला सकते हैं, न सोशल मीडिया पर शोर मचाकर खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रखवाला बताने वाले लोग। भारत की छवि को झूठे आरोपों, आधी-अधूरी जानकारी और राजनीतिक एजेंडे के सहारे चोट पहुंचाने का सपना देखने वालों को समझना होगा कि भारत कोई कमजोर देश नहीं, जिसकी साख चंद बयानों से मिटा दी जाए। भारत पर उंगली उठाने से पहले अपने तथ्यों की जांच करो, आरोप लगाने से पहले सबूत जुटाओ और लोकतंत्र का पाठ पढ़ने से पहले यह समझो कि भारत का भविष्य तय करने का अधिकार भारतीय जनता के पास है, किसी विदेशी नेता या सोशल मीडिया के स्वयंभू विशेषज्ञ के पास नहीं! सवाल पूछने हैं तो पूछिए, लेकिन सवालों की आड़ में देश की संस्थाओं को बदनाम करने का ठेका मत लीजिए। क्योंकि भारत की असली ताकत तिरिगे के नीचे खड़े करोड़ों लोगों का विश्वास, स्वाभिमान और अपने देश का फैसला खुद करने का अधिकार है।

फिल्म खत्म होने के बाद भी दर्शक के भीतर क्या बचा

पुस्तक समीक्षा

श्याम यादव की किताब 'फिल्म खत्म होने के बाद' सामान्य फिल्मी किताबों से अलग अपनी विषयवस्तु और दृष्टिकोण के कारण ध्यान खींचती है। आमतौर पर फिल्मों पर लिखी जाने वाली किताबें उनके कथानक, कलाकारों, निर्देशन, संगीत और तकनीकी पक्षों की चर्चा करती हैं। इसके विपरीत, यह किताब इस सवाल पर केंद्रित है कि फिल्म देखने के बाद दर्शक अपने साथ क्या लेकर सिनेमाघर से बाहर निकलता है।

फिल्म उसके भीतर कौन-से विचार जगाती है, जीवन को देखने की उसकी दृष्टि में क्या बदलाव लाती है और सामाजिक यथार्थ से उसका रिश्ता किस तरह बनता है किताब का मूल संरोकार इन्हीं सवालों से है। चार खंडों में विभाजित इस पुस्तक की विशेषता यह है कि लेखक फिल्मों को केवल मनोरंजन का माध्यम मानकर उनकी व्याख्या नहीं करते, बल्कि उनके प्रभाव और अंतर्निहित अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टि से किताब पाठक को फिल्मों के बारे में पहले से बनी धारणाओं से आगे जाकर सोचने का अवसर देती है। फिल्म का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसने दर्शक का कितना मनोरंजन किया, बल्कि इस कसौटी पर भी होना चाहिए कि उसने दर्शक को कितना संवेदनशील और विचारशील बनाया।

किताब की भाषा और शैली भी इसे प्रचलित फिल्मी लेखन से अलग करती है। इसमें पद्यात्मक प्रवाह या भावुक अभिव्यक्ति के बजाय गद्यात्मक विवेचन अधिक दिखाई देता है। यह शैली विषय को गंभीरता देती है, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। जो पाठक फिल्म संबंधी लेखन में रोचक किस्सों, सहज प्रवाह और भावनात्मक जुड़ाव की अपेक्षा करते हैं, उन्हें इसकी शैली कुछ हद तक नीरस लग सकती है। हालांकि, गंभीर पाठकों के लिए यही शैली विचारों पर ठहकर सोचने का अवसर भी बन सकती है।

पुस्तक की सबसे बड़ी कमी इसका चित्रविहीन होना है। फिल्मों पर आधारित किताब में एक भी फोटो न होना खटकता है। फिल्म में दृश्य माध्यम हैं और उनसे जुड़ी तस्वीरें पाठकीय अनुभव को समृद्ध करने के साथ चर्चा को अधिक जीवंत बना सकती थीं। कुल मिलाकर, 'फिल्म खत्म होने के बाद' फिल्मों को देखने के बजाय उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करती है। विषय की दृष्टि से यह एक सार्थक पहल है, लेकिन अधिक सहज भाषा और उपयुक्त चित्रों के समावेश को किताब पाठकों के व्यापक वर्ग तक बेहतर ढंग से पहुंच सकती थी।

समीक्षक

पुस्तक : फिल्म खत्म होने के बाद

लेखक : श्याम यादव

कीमत : ₹ 299

प्रकाशक : न्यू वर्ल्ड पब्लिकेशन , नई दिल्ली

प्रतिनिधिमंडल और समर्थकों की एक अनिवारित भीड़ सुप्रीम कोर्ट के भीतर स्थित फाइलिंग काउंटर तक पहुंच गई।एक ऐसे समय में जब कोर्ट की रजिस्ट्री अपने दैनिक कार्य को समेट रही थी, परिसर के भीतर अचानक पैदा हुए इस राजनीतिक कोलाहल, नारेबाजी और समर्थकों के हुजूम ने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक तंत्र को कुछ समय के लिए ठप कर दिया। इसके साथ ही, एक तकनीकी और कानूनी पहलू यह भी सामने आया कि इस संयुक्त याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 14 प्रक्रियात्मक खामियां पाई थीं।

न्याय की चौखट पर सियासत और संवैधानिक मर्यादा का संकट

(अशोक भाटिया)

चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई 'स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन' की कार्ययद को लेकर गठबंधन और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि इस विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के नाम पर देश भर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं।

भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 12 अक्टूबर 2026 की तारीख एक ऐसी असाधारण और चिंताजनक घटना के रूप में दर्ज हो चुकी है, जिसने संवैधानिक संस्थाओं के बीच पारस्परिक सम्मान की सीमाओं को पूरी तरह से धुंधला कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया के खिलाफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी और ईडिया गठबंधन के तमाम शीर्ष नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट परिसर तक निकाला गया विरोध मार्च सिर्फ एक राजनीतिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वह न्याय की सर्वोच्च देहरी पर जन-दबाव बनाने का एक ऐसा अभूतपूर्व प्रयास था, जिसकी अनुमति हमारा संवैधानिक ढांचा कभी नहीं देता। 15 अक्टूबर 2026 को इस संवेदनशील मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सुर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची की पीठ ने जो बेहद सख्त रुख अपनाया, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र की आत्मा उसकी संस्थाओं की गरिमा और उनकी स्वतंत्रता में

बसती है, न कि सड़कों पर उमड़ने वाली राजनीतिक भीड़ के कोलाहल में।

अदालत का सुनवाई के दौरान यह कहना कि हम आईएम टावर (हाथीदांत के मीनारों) में नहीं बैठें हैं, हमें सब पता है कि बाहर क्या बयान दिए जा रहे हैं और कोर्ट के भीतर क्या कहा जा रहा है, देश के पूरे राजनीतिक नेतृत्व के लिए एक गंभीर और ऐतिहासिक चेतावनी है। जब देश का विपक्ष का नेता, जिसके पास कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है और जो संसद के भीतर देश की जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है, स्वयं समर्थकों की भारी भीड़, नारेबाजी और हंगामे के बीच देश की सर्वोच्च अदालत की रजिस्ट्री में याचिका दाखिल करने पहुंचता है, तो यह सवाल उठाना लाजिमी है कि क्या अब न्यायिक प्रक्रियाओं का फैसला भी सड़कों के संख्याबल से तय होगा? यह संपादकीय इसी गहरे और गंभीर संवैधानिक संकट का निष्पक्ष विश्लेषण करने का प्रयास है कि आखिर विपक्ष के इस कदम के पीछे की राजनीति क्या है, न्यायपालिका की चिंताएं कितनी जायज हैं और भारतीय लोकतंत्र को इस अभूतपूर्व संस्थानत टकराव से बचाने के लिए किस तरह के संतुलन की आवश्यकता है।

इस पूरे विवाद की जड़ें किसी न्यायिक फैसले या अदालती आदेश में नहीं, बल्कि देश की चुनावी प्रक्रिया की शुचितता से जुड़ी हैं। चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में शुरू की गई स्पेशल इन्टेंसिव रिवीजन की कवायद को लेकर गठबंधन और एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि इस विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया के

नाम पर देश भर में करीब 13 करोड़ मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए हैं। विपक्ष इससे चोटों की चोरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश करार दे रहा है। इसी के विरोध में पिछले



सप्ताह दिल्ली की सड़कों पर विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए थे, जहां पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज ने आग में घी का काम किया था। राजनीतिक रूप से चुनाव आयोग के फैसलों का विरोध करना और उस पर सवाल उठाना विपक्ष ने न सिर्फ लोकतांत्रिक अधिकारों, बल्कि उसका कर्तव्य भी है। भारतीय चुनावी राजनीति में ईवीएम से लेकर मतदाता सूचियों में विसंगतियों के दावों तक, विपक्ष हमेशा से मुखर रहा है। इसी सिलसिले में जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तुषमूल काश्यप

की सुप्रीमो ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव सहित 13 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक संयुक्त रिट याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया, तो देश

को लगा कि यह लड़ाई अब पूरी तरह से कानूनी और संवैधानिक दायरे में लड़ी जाएगी। लेकिन, कानूनी याचिका दायर करने की सामान्य प्रक्रिया को जिस तरह से एक विशाल राजनीतिक जुलूस में तब्दील कर दिया गया, उसने इस कानूनी लड़ाई के वास्तविक उद्देश्य पर ही बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए।

12 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के लुटियंस जौन में जो दृश्य दिखाई दिए, वे देश के न्यायिक इतिहास में बेहद दुर्लभ और विचलित करने वाले थे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी

वाड़ा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, विपक्षी दलों के सांसद, छात्र संगठन और समर्थक संसद मार्ग से होते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर की ओर बढ़े। हालांकि सुरक्षा कारणों से पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी नेताओं का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल और समर्थकों की एक अनिवारित भीड़ सुप्रीम कोर्ट के भीतर स्थित फाइलिंग काउंटर तक पहुंच गई।एक ऐसे समय में जब कोर्ट की रजिस्ट्री अपने दैनिक कार्य को समेट रही थी, परिसर के भीतर अचानक पैदा हुए इस राजनीतिक कोलाहल, नारेबाजी और समर्थकों के हुजूम ने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक तंत्र को कुछ समय के लिए ठप कर दिया। इसके साथ ही, एक तकनीकी और कानूनी पहलू यह भी सामने आया कि इस संयुक्त याचिका में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने 14 प्रक्रियात्मक खामियां पाई थीं। इनमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पहचान पत्र का धुंधला होना, जरूरी प्राधिकरण दस्तावेजों का गायब होना और यहां तक कि कोर्ट फीस में 220 की कमी होना शामिल था। इन मामूली प्रक्रियात्मक त्रुटियों को दूर करने के बजाय, जिस तरह से नेताओं और कार्यकर्ताओं की फौज ने रजिस्ट्री पर दबाव बनाने की कोशिश की, उसने देश के जागरूक वकीलों और नागरिकों को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से जुड़े करीब 200 वकीलों ने तत्काल इस घटना का सज़ान लिया और पत्र लिखकर इस बात पर गहरी चिंता जताई कि देश की सर्वोच्च अदालत को राजनीतिक शक्ति-प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया जा रहा है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

शिक्षिका की अनुपस्थिति से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित, ग्रामीणों ने कलेक्टर से की शिकायत

एकल शिक्षक वाली शाला में नियमित अध्यापन नहीं होने का आरोप, कार्रवाई नहीं होने पर स्कूल में तालाबंदी की चेतावनी

कोंडगांव। जिले के विकासखंड कोंडगांव अंतर्गत ग्राम पंचायत जोबा के शासकीय प्राथमिक शाला बड़ेउसरी में पदस्थ प्रधान अध्यापिका श्रीमती वंदना दुबे के विरुद्ध ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। शाला प्रबंधन एवं विकास समिति और ग्राम के पालकों ने शिक्षिका पर बिना सूचना अनुपस्थित रहने, बच्चों की पढ़ाई के प्रति लापरवाही बरतने तथा पालकों के साथ अनुचित व्यवहार करने के आरोप लगाते हुए कलेक्टर को शिकायत सौंपी है। ग्रामीणों ने शिक्षिका के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करने और विद्यालय में नए शिक्षक की व्यवस्था करने की मांग की है।

बिना सूचना अनुपस्थित रहने का आरोप-शिकायत के अनुसार, 22 अक्टूबर



2026 को शाला प्रबंधन एवं विकास समिति तथा ग्रामीण पालकों ने विद्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधान अध्यापिका बिना किसी लिखित सूचना के अनुपस्थित पाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार उनके अनुपस्थित रहने की शिकायत सामने आई है और समझाझर देने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।

बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने की चिंता-ग्रामीणों ने शिकायत में उल्लेख किया है

कि विद्यालय में एक ही शिक्षक पदस्थ होने के कारण उनके अनुपस्थित रहने या अवकाश पर होने से बच्चों की पढ़ाई सीधे प्रभावित होती है। इसके अलावा, पालक-बालक बैठक आयोजित नहीं करने, पालकों से ऊंची आवाज में बात करने और शाला समय में बच्चों को पढ़ाने के बजाय मोबाइल फोन पर व्यस्त रहने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, शिक्षिका के लगभग दो महीने के अवकाश पर रहने की जानकारी भी सामने आई है।

कार्रवाई नहीं हुई तो तालाबंदी की चेतावनी- ग्रामीणों ने कलेक्टर से मामले की जांच कर प्रधान अध्यापिका के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने, उन्हें वर्तमान विद्यालय से अन्यत्र भेजने तथा नए शिक्षक की व्यवस्था करने की मांग की है। शिकायत में चेतावनी दी गई है कि यदि एक दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होती है, तो ग्रामवासी विद्यालय में तालाबंदी करने के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराने की बात भी कही गई है।

कई अधिकारियों को सौंपा आवेदन-इस मामले में कलेक्टर के अलावा खंड शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी को भी आवेदन सौंप जाने की जानकारी सामने आई है। शिकायत पर शिक्षा विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर ग्रामीणों की नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल, शिक्षिका के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। मामले में संबंधित शिक्षा अधिकारियों की जांच और शिक्षिका का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रधानमंत्री मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजयुमो ने फूंक पुतला



-कोंडगांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा, जिला कोंडगांव ने पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा मोर्चा के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए सार्वजनिक जीवन

में भाषा की मर्यादा बनाए रखने की मांग की। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग उचित नहीं है। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में पद की गरिमा और भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना

सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। विरोध प्रदर्शन में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनोज जैन, नगरपालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, मंडल अध्यक्ष कुलवंत चहल, जितेंद्र सुपाना, जैनेंद्र ठाकुर, लक्ष्मी ध्व सहित भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे उचित मूल्य दुकान संचालक

ई-पॉस मशीनें विभाज्य को सौंपने का ऐलान, स्थानीय से जिला स्तर तक की समस्याओं के निराकरण की मांग

बस्तर। संभाग के सभी जिले के उचित मूल्य दुकान संचालकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। संचालकों का कहना है कि लंबे समय से लंबित स्थानीय एवं जिला स्तरीय समस्याओं का समाधान नहीं होने के कारण उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हड़ताल के दौरान ई-पॉस मशीनें विभाज्य को सौंपने की भी घोषणा की गई है। संचालकों के इस फैसले से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित होने



की आशंका है। यदि हड़ताल लंबी चलती है, तो राशन के लिए उचित मूल्य दुकानों पर निर्भर रहने वाले हितग्राहियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब मांगों के निराकरण पर टिकी निगाहें-उचित मूल्य दुकान संचालकों ने स्पष्ट किया है कि उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाना आवश्यक है। ऐसे में अब संबंधित

विभाग और जिला प्रशासन के सामने संचालकों की मांगों पर गंभीरता से विचार कर समाधान निकालने की चुनौती है। अब देखना होगा कि 1 नवंबर से प्रस्तावित हड़ताल से पहले विभाग संचालकों से संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण करता है या फिर राशन वितरण व्यवस्था प्रभावित होने के बाद ही कोई पहल की जाएगी।

प्रधानमंत्री जी के दिवंगत पिता पर टिप्पणी से भड़का आक्रोश, नारायणपुर में भाजयुमो ने फूंक खड़गे का पुतला

नारायणपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वर्गीय पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पटना में की गई कथित अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भाजयुमो की जिला इकाई ने जयसंघ चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आयोजित प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने खड़गे का पुतला दहन कर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया।

भाजयुमो जिलाध्यक्ष परमानंद 'नानु' नाग ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के दिवंगत पिता को लेकर दिया गया बयान अत्यंत शर्मनाक और अमर्यादित है। दिवंगत पूर्वजों का सम्मान भारतीय सामाजिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध की भी एक



मर्यादा होती है और व्यक्तिगत एवं पारिवारिक टिप्पणियां लोकतांत्रिक शिष्टाचार के विपरीत है। नाग ने मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश से माफ़ी मांगने की मांग की।

प्रदर्शन में ये रहे उपस्थित: भाजपा जिलाध्यक्ष संघ्या पवार, बृजमोहन देवांगन, गौतम गोलछा, रमशीला नाग, पंकज जैन, जैकी कश्यप, संगीता जैन, पंकी उसेंडी, प्रशांत ठाकुर, अनुज जोशी, अनुराग पांडे, विनोद पात्र, दीपेन्द्र भोयर, हेमंत भुई, उज्ज्वल सोनी, सती ठाकुर, निलेश कौड़े, धर्मेन्द्र कुलदीप, भावेश सेठिया, अमित सेन, युधिष्ठिर मानकर, सौरभ मंडल, महेंद्र गोय और अनूप कुम्रेटी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

गुण्डाधूर महाविद्यालय में भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिलाई गई शपथ, ईमानदारी और पारदर्शिता पर दिया जोर

कोंडगांव। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2026 के अंतर्गत शासकीय गुण्डाधूर स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कोंडगांव में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के प्रति सतर्क रहने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करने की शपथ दिलाई गई। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सरला आत्राम की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉ. सरला आत्राम ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज, प्रशासन और राष्ट्र के विकास में बड़ी बाधा है। इसे समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण में ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और जवाबदेही को प्राथमिकता देनी चाहिए।



भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण की शुरुआत स्वयं से करनी होगी। कार्यक्रम के संयोजक अर्जुन सिंह नेताम ने संचालन किया। वहीं, शशिभूषण कन्नौजे ने सतर्कता जागरूकता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कार्यस्थल पर पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों को

बनाए रखने तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध समूहिक प्रयास करने की आवश्यकता बताई। इस अवसर पर डॉ. पुरोहित कुमार सोरी, शोभा राम यादव, डॉ. अल्का शुक्ला, रूपा सोरी, डॉ. देवाशीष हालदार, विनय देवांगन, नसीर अहमद, डॉ. आकाश वासनोकर,

समलेश पोटाई, लोचन सिंह वर्मा एवं हुमान यदु सहित महाविद्यालय के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के माध्यम से भ्रष्टाचार के प्रति शुच्य सहनशीलता अपनाने तथा ईमानदारी और सुशासन के मूल्यों को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।

बड़गांव में माड़िन नदी की पुलिया क्षतिग्रस्त, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा; प्रशासन और निको माइंस की अनदेखी पर उठे सवाल

नारायणपुर। जिले के छोटेंडोंगर क्षेत्र में बड़गांव स्थित माड़िन नदी की पुलिया की जर्जर स्थिति ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पुलिया के क्षतिग्रस्त हिस्से से सड़क के ऊपर लोहे की छड़ें निकल आई हैं। स्थानीय स्तर पर सामने आई तस्वीरों में पुलिया की खराब हालत साफ दिख गई है। इसके बावजूद रोजाना इस मार्ग से आवागमन जारी है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका जताई जा रही है। आमदई माइंस में चलने वाले भारी ट्रक और टिप्पर सहित बड़ी संख्या में वाहन इस मार्ग का उपयोग करते हैं। ऐसे में क्षतिग्रस्त पुलिया पर लगातार भारी वाहनों की आवाजाही से स्थिति और गंभीर होने की आशंका है। यदि समय-रहते मरम्मत नहीं कराई गई और पुलिया को नुकसान पहुंचा, तो नारायणपुर से छोटेंडोंगर और ओरछा की ओर आने-जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह मार्ग स्थानीय नागरिकों



के साथ-साथ वाहन चालकों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पुलिया बंद होने की स्थिति में दैनिक आवागमन, माल परिवहन और क्षेत्र की सामान्य

गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। पुलिया क्षतिग्रस्त होने और आवागमन बंद होने की स्थिति में ट्रक एवं टिप्पर मालिकों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। वाहनों की

किस्त, ढ़ाड़ियों का खर्च, रखरखाव और अन्य परिचायन लागत जारी रहने के कारण परिवहन व्यवसायियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। स्थानीय स्तर पर यह सवाल भी उठ रहा है

विचारक्रांति अभियान के तहत होगा आयोजन, पांचों विकासखंडों के गायत्री परिजन मिलकर संभालेंगे जिम्मेदारी

कोंडगांव में 24 दिसंबर से सजेगा पांच दिवसीय विराट पुस्तक मेला, 10 समितियों के गठन की तैयारी

कोंडगांव। गायत्री परिवार द्वारा विचारक्रांति अभियान के अंतर्गत कोंडगांव में पांच दिवसीय विराट पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 24 से 28 दिसंबर तक आयोजित होगा। आयोजन का उद्देश्य लोगों तक जीवनोपयोगी साहित्य पहुंचाना तथा विचारों के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन का संदेश देना है। युग निर्माण योजना, मधुरा के तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस पुस्तक मेले की तैयारियों को लेकर चिखलपुटी आश्रम, कोंडगांव में जिला स्तरीय गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें जिला समन्वय समिति कोंडगांव ने मेले के सफल संचालन के लिए विभिन्न समितियों के गठन की प्रक्रिया शुरू की। पुस्तक मेले का आयोजन जिला समन्वय समिति कोंडगांव द्वारा किया जाएगा। इसमें कोंडगांव, बड़ेराजपुर, माकड़ी,



केसकाल और परसगांव विकासखंडों के गायत्री परिजन सहयोग करेंगे।

विभिन्न समितियों को सौंपी गई जिम्मेदारी
आयोजन के सुचारु संचालन के लिए संयोजक समिति में कवल सिंह पांडे, भन सिंह नेताम, रूप सिंह लामा, सौ.आर. मरकाम और युधुज्य चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। सुरक्षा समिति में उल्लिल बघेल एवं महकाल (प्रदीप) शामिल हैं। स्वागत समिति में उमरूम मरकाम, धरुम पटेल, श्रीमती हुमन पटेल और श्रीमती दीपमाला केरुच को दायित्व सौंपा गया है। मंच व्यवस्था समिति में भरत सिंह, केजूराम नेताम और श्रीमती अश्विका मरकाम शामिल हैं। यही, पूरा व्यवस्था समिति की जिम्मेदारी रोमचंद्र कोराम और भाव सिंह कश्यप को दी गई है। मीडिया व्यवस्था समिति में राजुराम पांडे, योगेश पटेल और राजेश साह को शामिल किया गया है। पुस्तक स्टोर व्यवस्था समिति में नारायण ठाकुर, शिव सिंह मरकाम, रवि सेना और रामसुख मरकाम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आयोजन समिति के अनुसार, पैमेंट काउंटर, भोजन-नाश्ता व्यवस्था तथा डिजिटल बुक एवं पीडब्ल्यू काउंटर से संबंधित समितियों के सदस्यों की सूची शीघ्र घोषित की जाएगी।

जीवनोपयोगी साहित्य प्राप्त करने का मिलेगा अवसर-
गायत्री परिवार के मुख्य दृष्टी उद्देश्य साहू ने बताया कि विराट पुस्तक मेले के माध्यम से क्षेत्रवासियों को जीवनोपयोगी साहित्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने सभी गठित समितियों के सदस्यों से अपने दायित्वों का निर्वहन समय पर और समर्पण भाव से करने की अपील की, ताकि आयोजन सफलापूर्वक संचाल हो सके।

बेमेतरा में 29 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला, 500 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

बेमेतरा/- जिले के बेरोजगार एवं रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 29 अक्टूबर 2026, गुरुवार को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। यह मेला शासकीय पंडित जवाहर लाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय के रसा भवन, बेमेतरा में आयोजित होगा। मेले के माध्यम से विभिन्न पदों पर 500 से अधिक रिक्तियों के लिए भर्ती की जाएगी। जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आयोजित इस रोजगार मेले का उद्देश्य इच्छुक अर्थवर्धियों और निजी क्षेत्र के नियोजकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना है। रोजगार कार्यालय नियोजकों एवं आवेदकों के बीच एक मंच उपलब्ध कराता है, जिससे योग्य अर्थवर्धियों को रोजगार के अवसर मिल सकें। यह भर्ती केवल निजी क्षेत्र की संस्थाओं में कार्य करने के लिए की जाएगी।

आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचें अभ्यर्थी
रोजगार मेले में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार कार्यालय का पंजीयन पत्र, छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा समस्त शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र साथ लेकर उपस्थित होना होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगा आयोजन-रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 29 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक शासकीय पंडित जवाहर लाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रसा भवन, बेमेतरा में पहुंच सकते हैं।

संक्षिप्त समाचार

शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आबंटन हेतु आवेदन 30 अक्टूबर तक

बिलासपुर। जिले के मस्तुरी विकासखण्ड अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य दुकान शिवटिकारी, वेद परसदा एवं मड़ई के नवीन आबंटन के लिए 30 अक्टूबर 2026 तक शाम 5 बजे तक बंद लिफाफे में आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। ग्राम पंचायत एवं स्थानीय नगरीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, प्राथमिक कृषि साख समितियां, अन्य उपभोक्ता सहकारी समितियां, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम, वृहदाकार आदिम जाति बहुदेशीय सहकारी समिति (लेम्पस) एवं वन सुरक्षा समितियों के आवेदन ही स्वीकार किये जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ संस्था के पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि, बैंक खाते की सत्यापित प्रतिलिपि, विगत 3 माह का बैंक स्टेटमेंट, दुकान संचालन संबंधी संस्था द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रतिलिपि, संस्था द्वारा विगत तीन माह में की गई गतिविधियों के संबंध में समूह का कार्यवाही, प्रस्ताव पंजी की सत्यापित प्रतिलिपि एवं संस्था प्रमुख द्वारा आवेदन के संबंध में निष्पादित शपथ पत्र मूलतः संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन अथवा दस्तावेज पूर्ण नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त होने पर आवेदक संस्था जिम्मेदार होंगे।

मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के लिए पंजीयन एवं सत्यापन 31 अक्टूबर तक

गौरैला-पेंड्रा-मरवाही। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना वर्ष 2026-27 के अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं आवेदनों के सत्यापन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित की गई है। जिले से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कुल 48 विद्यार्थियों के नाम मेरिट सूची में शामिल हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि पंजीयन एवं सत्यापन के लिए राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर 8 अक्टूबर से लिंक उपलब्ध है। विद्यार्थी पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर मेरिट सूची एवं आवश्यक दिशा-निर्देश देख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के अनुक्रमांक से स्वयं पंजीयन कर स्थायी जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र के आवेदन संदर्भ क्रमांक का उपयोग करते हुए आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विद्यार्थी का महाविद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है। इसके लिए पोर्टल पर उपलब्ध बोनाफाइड प्रमाण पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर संबंधित महाविद्यालय से प्रमाणित कराना होगा। प्रमाणित पत्र एवं महाविद्यालय की फीस रसीद अपलोड करने के साथ बैंक खाते की जानकारी दर्ज कर पूर्ण आवेदन कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने वाले विद्यालय को भेजना होगा। आवेदनों का सत्यापन पहले संबंधित विद्यालय और उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

खाद्य निरीक्षकों के प्रभार क्षेत्रों में बदलाव, नवीन पदस्थापना आदेश

गौरैला-पेंड्रा-मरवाही। कलेक्टर श्री विजय दयाराम के. ने जिले के पांच खाद्य निरीक्षकों की पदस्थापना एवं प्रभार क्षेत्रों में परिवर्तन का आदेश जारी किया है। कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा के पूर्व 14 नवंबर 2024 में आंशिक संशोधन करते हुए आगामी आदेश तक नई व्यवस्था लागू की गई है। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जारी आदेश के अनुसार खाद्य निरीक्षक श्री जितेन्द्र वासुदेव को अनुविभाग पेंड्रारोड में पदस्थ करते हुए विकासखंड गौरैला के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों की शासकीय उचित मूल्य दुकानों का प्रभार सौंपा गया है। वे पूर्व में विकासखंड पेंड्रा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों का प्रभार संभाल रहे थे। श्री राहुल सिंह राजपूत को अनुविभाग मरवाही में पदस्थ करते हुए विकासखंड मरवाही की निर्धारित शासकीय उचित मूल्य दुकानों का प्रभार दिया गया है। वे पूर्व में विकासखंड गौरैला के ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के प्रभारी थे। उनके नवीन प्रभार में दुकान आईडी 402010001 से 402010017, 402010019 से 402010023, 402010044 से 402010059, 402010074, 402010075, 402010077, 642010078, 642010080 से 642010085, 642010089 एवं 642010090 शामिल हैं। कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा में पदस्थ सुश्री नेहा पाटले को अनुविभाग मरवाही/पेंड्रारोड में पदस्थ करते हुए विकासखंड मरवाही की दुकान आईडी 402010018, 402010024 से 402010043, 402010060 से 402010073, 402010076, 642010079, 642010086 एवं 642010087 का प्रभार सौंपा गया है। श्री आशीष पाण्डेय को अनुविभाग मरवाही से अनुविभाग पेंड्रारोड में पदस्थ करते हुए विकासखंड पेंड्रा के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की समस्त शासकीय उचित मूल्य दुकानों का प्रभार दिया गया है। उनके पूर्व प्रभार वाली मरवाही की निर्धारित दुकानों की जिम्मेदारी अब श्री राहुल सिंह राजपूत संभालेंगे। श्री अरविन्द चंद्रा कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा में पदस्थ रहते हुए विकासखंड गौरैला के शहरी क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य दुकानों का प्रभार संभालेंगे।

जसकरण सिंह के पांच गोलों के बावजूद बैलाडीला बुल्स जीत से दूर, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने 5-5 से ड्रॉ कराया मुकाबला

■ छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में रोमांचक मुकाबला, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने हासिल किया पहला अंक

■ जसकरण सिंह बने ‘प्लेयर ऑफ़ द मैच’, अंकतालिका में बैलाडीला बुल्स चौथे और संस्कारधानी स्ट्राइकर्स पांचवें स्थान पर

बिलासपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ हॉकी लीग में आज खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में संस्कारधानी स्ट्राइकर्स और बैलाडीला

बुल्स के बीच मैच 5-5 से ड्रॉ रहा। बैलाडीला बुल्स के जसकरण सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अकेले पांच गोल दागे, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। वहीं, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने जबरदस्त संघर्ष करते हुए मुकाबला बराबरी पर समाप्त किया और प्रतियोगिता में अपना पहला अंक हासिल किया। शमशेर और चिंगलेनसाना सिंह के नेतृत्व वाली दोनों टीमों की टूर्नामेंट में अब भी अपनी पहली जीत का इंतजार है। यह मुकाबला रोमांचक उतार-चढ़ाव और खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के लिए यादगार बन गया। विधायक श्री धरमलाल कोशिक, सराडा के हेड ऑफ ऑपरेशंस श्री मनोज शाह और छत्तीसगढ़ जुड़ो संघ के अध्यक्ष श्री अरुण द्विवेदी भी इस रोमांचक मैच को देखने मौजूद थे। मैच के दोनों हाफ में खेल का अलग-अलग



रंग देखने को मिला। पहले हाफ में संस्कारधानी स्ट्राइकर्स का दबदबा रहा। आर्यन खेस और आशीष तानी पूर्ति ने शानदार गोल दागकर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लेकिन दूसरे हाफ में जसकरण सिंह ने अपने आक्रामक

की टीम बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही थी और बैलाडीला बुल्स का आक्रमण पूरी तरह बेअसर नजर आ रहा था। लेकिन कुछ ही देर में परिस्थितियां बदल गईं। स्ट्राइकर्स की रक्षापंक्ति दबाव में आ गई, जिसका फायदा उठाते हुए बुल्स ने लगातार दो गोल दागकर स्कोर बराबर कर दिया। मैच समाप्त होने में केवल पांच मिनट शेष थे और स्कोर 4-4 की बराबरी पर था। ऐसा लग रहा कि मुकाबला इसी स्कोर पर समाप्त होगा, लेकिन जसकरण सिंह ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उन्होंने शानदार टॉमहॉक शॉट लगाकर अपना पांचवां गोल दागा और बैलाडीला बुल्स को 5-4 की बढ़त दिला दी। हालांकि, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने हार नहीं मानी। मैच समाप्त होने से महज दो मिनट पहले मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्ट्राइकर्स ने स्कोर 5-5 से बराबर कर दिया।

राइस मिलर्स की बैठक में चावल जमा की प्रगति और धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा

धान और चावल की रीसाइविलिंग बर्दाश्त नहीं होगी : कलेक्टर

■ बारदाना शीघ्र जमा करने के निर्देश, एफ़सीआई में 15 दिनों से अधिक लंबित स्टोक की होगी जांच

बिलासपुर/ संवाददाता

कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल ने राइस मिलर्स को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि धान एवं चावल की रीसाइविलिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धान उपाजर्जन, मिलिंग और चावल जमा करने की पूरी प्रक्रिया में नियमों का पालन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने आगामी धान खरीदी के लिए आवश्यक बारदाना शीघ्र जमा करने तथा भारतीय खाद्य निगम में 15 दिनों से अधिक समय से लंबित स्टोक के मामलों की जांच करने के निर्देश दिए। कलेक्टर की अध्यक्षता में आज आयोजित जिले के राइस मिलर्स की बैठक में चावल जमा की प्रगति, मिलिंग संबंधी समस्याओं और खरीफविपणन वर्ष 2026-27 की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि



उपाजर्जन एवं मिलिंग व्यवस्था में अनियमितताओं को रोकने के लिए संबंधित अधिकारी सतर्कता बरतें। मिलर्स निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुरूप कार्य करें। आगामी धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आवश्यक बारदाने की उपलब्धता समय पर सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

जिले में 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी प्रारंभ होना प्रस्तावित है। इसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने मिलर्स को बारदाना जल्द जमा करने और संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय से सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। भारतीय खाद्य निगम में चावल जमा की स्थिति की समीक्षा के

दौरान कलेक्टर ने 15 दिनों से अधिक समय से लंबित स्टोक वाले मिलर्स के मामलों की जांच का जिम्मा खाद्य नियंत्रक को सौंपा। उन्होंने लंबित मामलों में आवश्यक कार्रवाई करते हुए चावल जमा की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा की प्रगति तथा अन्य जिलों में निगम के अंतर्गत चावल जमा करने की स्थिति पर भी चर्चा हुई। चावल में 10 प्रतिशत ब्रोकेन की निर्धारित सीमा से संबंधित विषयों और मिलर्स की समस्याओं की जानकारी ली गई। कलेक्टर ने विगत धान खरीदी वर्ष में मिल सत्यापन के दौरान कमियां पाए जाने वाले राइस मिलर्स के मामलों की भी समीक्षा की। उन्होंने मिलिंग और चावल जमा से जुड़े कार्यों में निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद्य नियंत्रक श्री अमृत कुजूर, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम श्री निरिन दीवान, भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक श्री अनूप कुमार, जिला विपणन अधिकारी श्री उपेंद्र खांडे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी और जिले के राइस मिलर्स उपस्थित थे।

छग राज्योत्सव 2026 में हवाई करतब दिखाने रायपुर पहुँची सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम...

रायपुर/ संवाददाता

भारतीय वायु सेना की सारंग हेलीकॉप्टर प्रदर्शन टीम छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित तीन दिवसीय राज्योत्सव 2026 में भाग लेने के लिए आज रायपुर पहुँची। टीम नवा रायपुर अटल नगर स्थित संघ झील क्षेत्र के ऊपर शानदार हवाई प्रदर्शन से दर्शकों को रोमांचित करेगी। स्वदेश में विकसित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एलएच) ‘ध्वज’ से उड़ान भरने वाली सारंग टीम अपनी सटीक उड़ान, समन्वित संरचनाओं और रोमांचक हवाई करतबों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रदर्शन भारतीय वायु सेना के उत्कृष्ट उड़ान कौशल, अनुशासन, टीम भावना और पेशेवर दक्षता के साथ भारत की स्वदेशी हेलीकॉप्टर क्षमताओं को भी प्रदर्शित करेगा। यह



आयोजन नागरिकों, विद्यार्थियों, युवाओं और विमानन में रुचि रखने वालों को हेलीकॉप्टरों की सामूहिक उड़ान में सटीकता और आपसी तालमेल देखने का अवसर प्रदान करेगा। राज्योत्सव में सारंग की भागीदारी समारोह के आकर्षण को बढ़ाने के साथ भारतीय वायु सेना और छत्तीसगढ़ के नागरिकों के बीच जुड़ाव को और सुदृढ़ करेगी। मोर से प्रेरित

महतारी वंदन योजना बनी वैसाखी बाई का सहारा, छोटी-छोटी जरूरतों से संवर रहा परिवार का भविष्य

मरवाही/ संवाददाता

परिवार की खुशहाली केवल बड़े संसाधनों से नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों के समय पर पूरा होने से भी आती है। छत्तीसगढ़ शासन की महतारी वंदन योजना महिलाओं के जीवन में इसी तरह सकारात्मक बदलाव ला रही है। गौरैला विकासखंड की ग्राम पंचायत धनौली के ढाढ़ीपारा निवासी श्रीमती वैसाखी बाई के लिए यह योजना परेलू जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अपने बच्चे की पढ़ाई में सहयोग देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गई है। महतारी वंदन योजना की 32वीं किस्त की राशि प्राप्त होने से वैसाखी बाई को आर्थिक संबल मिला है। वे इस राशि का उपयोग अपने लिए साग-सब्जी खरीदने तथा अपने बच्चे की



पढ़ाई पर होने वाले खर्च में करती हैं। उनके लिए योजना की यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने और बच्चे की शिक्षा में योगदान देने का अवसर भी है। घर-परिवार की जिम्मेदारियों के बीच महिलाओं के लिए अपनी आवश्यकताओं और बच्चों की पढ़ाई के खर्च का ध्यान रखना आसान नहीं होता। ऐसे में नियमित आर्थिक सहायता उन्हें

अपने छोटे-छोटे फैसले स्वयं लेने और परिवार की जरूरतों में सहयोग करने का भरोसा देती है। वैसाखी बाई की कहानी इसी भरोसे और आत्मनिर्भरता की एक सहज मिसाल है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से मिलने वाली सहायता राशि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ ही परिवार के पोषण और बच्चों की शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों में सहयोग दे रही है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आदिकवि महर्षि वाल्मीकि जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न



रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय (कुशाभाऊ ठाकरे परिसर) में सोमवार को महाकाव्य रामायण के रचयिता आदिकवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा की राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी स्मृति इरानी तथा राष्ट्रीय मंत्री व प्रदेश सह प्रभारी सिद्धार्थ शम्भू ने पुष्पांजलि कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं पदाधिकारियों के साथ महर्षि वाल्मीकि के तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके आदर्शों को स्मरण किया। इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री हृथ अखिलेश सोनी व डॉ. नवीन मार्कण्डेय, प्रदेश कार्यालय मंत्री अशोक बजाज सहित प्रदेश पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता प्रमुख शेष थे और स्कोर 4-4 की बराबरी पर था। ऐसा लग रहा कि मुकाबला इसी स्कोर पर समाप्त होगा, लेकिन जसकरण सिंह ने एक बार फिर कमाल दिखाया। उन्होंने शानदार टॉमहॉक शॉट लगाकर अपना पांचवां गोल दागा और बैलाडीला बुल्स को 5-4 की बढ़त दिला दी। हालांकि, संस्कारधानी स्ट्राइकर्स ने हार नहीं मानी। मैच समाप्त होने से महज दो मिनट पहले मिले पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्ट्राइकर्स ने स्कोर 5-5 से बराबर कर दिया।

प्रभारी श्रीमती इरानी ने इस मौके पर प्रदेशवासियों को आदि कवि, ज्ञान, समरसता और तपस्या के पावन प्रतीक महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि ‘महर्षि वाल्मीकि केवल रामायण के रचनाकार ही नहीं, अपितु भारतीय सनातन संस्कृति और सामाजिक समरसता के मूल स्तंभ हैं। जब विश्व में साहित्य और सभ्यताएँ अपनी शैशवावस्था में थीं, तब महर्षि वाल्मीकि ने हमें ‘रामायण’ जैसा अलौकिक महाकाव्य दिया। उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र के माध्यम से धर्म, कर्तव्य, न्याय, मातृ-पितृ भक्ति और लोक-कल्याण का शाश्वत मार्ग प्रशस्त किया। महर्षि वाल्मीकि का जीवन दर्शन हमें सिखाता है कि संकल्प, साधना और ईश्वर भक्ति से व्यक्ति का आंतरिक रूपान्तरण संभव है और कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से महान बन सकता है। उनका संदेश वर्ग-विहीन, समतामूलक और मर्यादापूर्ण समाज के निर्माण की प्रेरणा देता है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी श्रीमती इरानी ने इस अवसर पर कहा कि ‘‘आज जब हमारा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मूलमंत्र पर आगे बढ़ रहा है।

श्री गायत्री प्रज्ञा पीठ भटगांव में व्यक्तित्व निर्माण युवा एवं

नारी सशक्तिकरण प्रशिक्षण शिविर संपन्न

● 300 से भी अधिक युवा, महिला एवं गायत्री परिजन इस प्रशिक्षण में हिस्सा लिया

भटगांव. अखिल विश्व गायत्री परिवार, शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वावधान में श्री गायत्री प्रज्ञा पी में एक दिवसीय निःशुल्क व्यक्तित्व निर्माण, युवा एवं नारी सशक्तिकरण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन बड़े हर्षांखस के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य गुरुदेव पं. श्रीराम शर्मा आचार्य एवं वंदनीया माताजी भगवती देवी के चित्र पर दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण एवं पूजन से हुआ। इस दौरान शशिकांत साहू एवं महिला मंडल की सदस्यों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजन संपन्न कराया। गायत्री परिवार की मातृशक्ति बड़ी संख्या में गायत्री परिवार की सदस्यों, कालेज एवं कोचिंग संस्थान के बच्चे इस शिविर में बड़ी संख्या में शामिल होकर शिविर का लाभ उठाया। वहीं कार्यक्रम के स्वागत वंदन एवं देवपूजन के साथ कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ और लगभग 10:00 से 12:00 बजे – व्यक्तित्व निर्माण शशिकांत साहू द्वारा, 12:00 से 1:00 बजे तक परिवार निर्माण प्रशिक्षण छाया पटेल



द्वारा, 2:00 से 4:00 बजे तक आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी का प्रशिक्षण – पुष्पा वर्मा द्वारा एवं 4:00 से 5:00 बजे – नारी जागरण एवं स्वास्थ्य प्रबंधन का प्रशिक्षण – पिंकी रजक द्वारा दिया गया।

वहीं 5:00 से 6:00 बजे – विदाई एवं आभार कार्यक्रम सम्पन्न हुआ जहाँ नगर पंचायत उपाध्यक्ष प्रदीप देवांगन, एलडरमेन तुलसी आदित्य, पटेल समाज के प्रान्त अध्यक्ष सुरेंद्र पटेल, साई सेवा समिति के प्रमुख पंकज दुबे, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह दीक्षित, फूलचंद जायसवाल, सुरेश केशरवानी, रामदुलार साहू, गायत्री प्रज्ञा पीठ के संस्थापक बोधीराम साहू द्वारा ने अपने वाणी व उद्बोधन से कार्यक्रम की सराहना की।



इस दौरान उपस्थित सभी माताओं-बहनों और युवतियों ने बड़े ध्यान से प्रशिक्षण को सुना और अपनी नोटबुक में महत्वपूर्ण बातें लिखीं, वहीं कार्यक्रम का मुख्य संदेश रहा – हम बदलेंगे, युग बदलेगा – हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा और शालीन युवा श्रेष्ठ राष्ट्र, स्वस्थ युवा सबल राष्ट्र – सुसंस्कारित युवा, सशक्त नारी, समृद्ध समाज।

कलेक्टर का आदेश बेअसर: बरसात बीते एक महीना, बलौदा बाजार की खस्ताहाल सड़कों पर अब तक नहीं शुरू हुआ सुधार कार्य



बलौदाबाजार। जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग तथा नगर पालिका की लापरवाही के कारण बलौदाबाजार शहर सहित पूरे जिले की सड़कें बदहाली के आँसू रो रही हैं। पिछले महीने ही कलेक्टर ने सख्त लहजे में PWD और नगर पालिका के आला अधिकारियों को निर्देशित किया था कि बारिश समाप्त होते ही बलौदाबाजार नगर और जिले की सभी जर्जर व खराब सड़कों का तत्काल मरम्मत व सुधार कार्य शुरू किया जाए। हैरानी की बात यह है कि मानसून की विदाई हुए और बरसात समाप्त हुए लगभग एक महीना बीत चुका है, लेकिन कलेक्टर का यह आदेश पूरी तरह बेअसर साबित हो रहा है। जमीनी स्तर पर अभी तक किसी भी खराब सड़क की सुध नहीं ली गई है और न ही कहीं सुधार कार्य चालू हुआ है।

हादसों को न्योता दे रहें मुख्य सड़कें-स्थानीय नागरिकों और राहगीरों के अनुसार, बिलासपुर रोड (करही चौक से शिवनाथ नदी तक), भाटापारा रोड और शहर के भीतर की लगभग सभी अंदरूनी सड़कें गह्रों में तब्दील हो चुकी हैं। इन प्रमुख मार्गों पर चलना जान जोखिम में डालने जैसा है। त्योहारों और आम दिनों में इन रास्तों पर भारी ट्रैफिक रहता है, जिससे हर वक दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इन सड़कों को तत्काल प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना बेहद आवश्यक है।

वरिष्ठ वकील सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने जताई गहरी चिंता-बलौदाबाजार के वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश चंद्र श्रीवास्तव ने इस बदहाली पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त

करते हुए कहा, कलेक्टर का आदेश स्वागत योग्य था, लेकिन अधिकारियों की लचर कार्यप्रणाली के कारण आज जनता परेशान है। बरसात खतम हुए महीना भर हो गया, फिर भी करही चौक से शिवनाथ नदी मार्ग और भाटापारा रोड जैसी मुख्य सड़कों की मरम्मत शुरू न होना पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की घोर लापरवाही को दर्शाता है। धूल के गुबार और जानलेवा गह्रों से शहरवासी त्रस्त हैं। प्रशासन को तुरंत सज्जन लेकर ठेकेदारों और अधिकारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए और युद्धस्तर पर काम शुरू करवाना चाहिए। अब देखना यह होगा कि कुंभकर्णी नींद में सोए नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी कब जागते हैं और कलेक्टर के आदेश का पालन करते हुए जनता को इन बदहाल सड़कों से मुक्ति दिलाते हैं।

रबी 2026 में फसल विविधीकरण एवं वैकल्पिक खेती को बढ़ावा देने कृषि विभाग की तकनीकी कार्यशाला आयोजित

● द्वि-फसलीय क्षेत्र के विस्तार, अनुबंध खेती एवं किसानों की आय बढ़ाने के लिए बनाई जाएगी कार्ययोजना

राजनांदगांव। रबी वर्ष 2026 में जिले में द्वि-फसलीय क्षेत्र को बढ़ावा देने, किसानों को वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने तथा फसल विविधीकरण के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में कृषि विभाग के साथ उद्यानिकी, मत्स्य पालन एवं पशुपालन विभाग, सहकारी संस्थाओं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, कृषि क्षेत्र से जुड़े निजी कंपनियों के प्रतिनिधियों, कृषि



विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों, मैदानी अधिकारियों एवं किसान मित्रों ने सहभागिता की। कार्यशाला में रबी मौसम में किसानों द्वारा ली जाने वाली विभिन्न फसलों के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने, उपलब्ध सिंचाई जल का समुचित उपयोग करने, फसल चक्र में परिवर्तन लाने तथा किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से तकनीकी सत्र आयोजित

किए गए। अधिकारियों ने किसानों की भूमि, सिंचाई की उपलब्धता, स्थानीय परिस्थितियों एवं बाजार की संभावनाओं के अनुरूप फसल चयन और फसल विविधीकरण की कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री दुर्गा प्रसाद अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने किसानों को पारंपरिक फसल पद्धतियों के साथ वैकल्पिक फसलों को अपनाने, कृषि

क्षेत्र में नवाचार करने तथा उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आय बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण से कृषि संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और किसानों के आर्थिक हितों को मजबूत करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए। उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने गत वर्ष जिले में फसल विविधीकरण के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की जानकारी देते हुए सभी मैदानी अधिकारियों एवं किसान मित्रों से किसानों के बीच पहुंचकर व्यापक चर्चा करने तथा क्षेत्रवार कार्ययोजना तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि फसल चयन करते समय जल की मांग, सिंचाई की उपलब्धता, भूमि की प्रकृति एवं बाजार की संभावनाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है।

चक्रवाती तूफान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना, किसानों को सतर्क रहने की सलाह

बेमेतरा। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आगामी दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर ने किसानों के लिए मौसम आधारित कृषि सलाह जारी की है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम और कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी ने विभाग के अधिकारी-कर्मचारी सहित मैदानी अमले को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। इस दौरान हवा की गति 115 से 140



किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना है। जिला-वार पूर्वानुमान: 25 अक्टूबर: बस्तर, देतेवाड़ा, सुकमा में अत्यधिक भारी वर्षा, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव में भारी बारिश 26 अक्टूबर: दुर्ग, बालोद,

राजनांदगांव, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, कोंडागांव, कांकेर, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, सुकमा सहित विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा 28 एवं 29 अक्टूबर: प्रदेश के सभी जिलों में वर्षा, कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश।

कृषि वैज्ञानिकों की सलाह: 1. धान, दलहन, तिलहन की पक चुकी फसलों की कटाई 2 से 4 दिन तक रोकें। 2. कटी हुई फसल को तुरंत सुरक्षित, सूखे स्थान पर रखें, तिरपाल से ढकें। 3. खेतों में जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें। 4. बारिश के दौरान कीटनाशक/कवकनाशक का छिड़काव न करें, मौसम साफ होने के बाद ही करें। 5. रबी फसलों की बुवाई नवंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू करें। 6. केरला, लौकी जैसी लता वाली सब्जियों और केले के पौधों को सहारा दें। 7. पशुओं को सूखे-सुरक्षित स्थान पर रखें, पेड़ों के नीचे न बांधें, सूखा चारा और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखें। किसान भाई मौसम पूर्वानुमान पर लगातार नजर रखें और समय रहते सावधानी बरतें।

आयुक्त ने सिंचाई नाली निर्माण कार्य का किया निरीक्षण

बलौदाबाजार। आयुक्त वी बी – जी रामजी तारन प्रकाश सिन्हा ने रविवार को जिला प्रवास के दौरान जनपद पंचायत सिमगा अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडुआ में संचालित कच्ची सिंचाई नाली निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर 157 श्रमिक नियोजित पाए गए। ने श्रमिकों से सीधे संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया। आयुक्त सिन्हा ने श्रमिकों से मजदूरी भुगतान, रोजगार उपलब्धता एवं कार्यस्थल से संबंधित समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को योजना अंतर्गत कार्य में अधिक से अधिक श्रमिकों



का नियोजन तथा कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिये। इस मैदानी निरीक्षण से न केवल श्रमिकों में उत्साह एवं विश्वास का संचार करेगा, बल्कि मांग आधारित रोजगार सृजन, श्रमिक नियोजन में वृद्धि तथा स्वीकृत कार्यों के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को भी नई गति प्रदान करेगा।

गजरा देवी तिवारी का निधन

बेमेतरा। ग्राम झिरिया निवासी स्व. श्री फालाल तिवारी की धर्मपत्नी श्रीमती गजरा देवी तिवारी का आज दिनांक 25 अक्टूबर 2026 को दोपहर लगभग 2 बजे 96 वर्ष की अवस्था में देवलोकगमन हो गया। स्व. गजरा देवी तिवारी अपने पीछे भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं। वे अशोक तिवारी, शिव तिवारी, ललित तिवारी और अखिलेश तिवारी की माता श्री थीं। उनकी अंतिम यात्रा आज पिकरी बेमेतरा मुक्तिधाम में किया गया।



महापौर ने 86.84 लाख के बी.टी. रोड रनिवल कार्यों का किया भूमिपूजन

● दुर्ग शहर में सड़क विकास को मिलेगी नई रफ्तार

दुर्ग। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र में नागरिकों को बेहतर सड़क एवं आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न बाड़ों में बी.टी.रोड रनिवल डामरीकरण एवं सड़क नवीनीकरण कार्यों का भूमिपूजन किया गया। महापौर अलका बाघमार ने सभापति श्याम शर्मा, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, वार्ड पार्षद एवं नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले, शेखर चन्द्राकर, आशीष चन्द्राकर, मनीष कोठारी, रंजीता पाटिल, युवराज कुंजम, अजित वैध, उप अभियंता कारण यादव सहित बड़ी संख्या में नागरिक की मौजूदगी में वार्ड क्रमांक 10, 11 एवं 13 में 15वें वित्त आयोग मद से स्वीकृत सड़क नवीनीकरण कार्यों का भूमिपूजन



दुर्गा चौक से बुद्ध विहार तक तथा वार्ड क्रमांक 11 में शंकर नगर बुद्ध विहार चौक से कुर्मी भवन एवं अन्य स्थानों तक बी.टी. रोड रनिवल कार्य कराया जाएगा। इन कार्यों की कुल स्वीकृत लागत राशि 42.20 लाख है। सड़क नवीनीकरण से संबंधित क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ ही नागरिकों को बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी। इसी क्रम में वार्ड क्रमांक 13 में भी 15वें वित्त आयोग मद से स्वीकृत विभिन्न बी.टी. रोड रनिवल कार्यों का भूमिपूजन किया गया। इसके अंतर्गत मोहन नगर में कश्यप के घर से ईश्वर वर्मा के घर तक, आकाश

दानी गली से लाल बिल्डिंग हैडपंप होते हुए शीलता मंदिर तक तथा गुप्ता नर्सिंग होम से चंद्राकर के घर तक सड़क नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों की कुल लागत राशि 44.64 लाख है। इस प्रकार वार्ड क्रमांक 10, 11 एवं 13 में कुल 86.84 लाख की लागत से सड़क नवीनीकरण कार्य कराए जाएंगे। इन कार्यों के पूर्ण होने से संबंधित क्षेत्रों में सड़क की स्थिति बेहतर होगी तथा आम नागरिकों, वाहन चालकों और स्थानीय रहवासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में

नवागढ़ में गूंजी लोककला की आवाज, गाबो बजाबो गोठियाबो को मिला बड़ा मंच

बेमेतरा। वरिष्ठ लोक कलाकार बेमेतरा जिले के ग्राम जेवरा के मूल निवासी राकेश तिवारी जो छाल की लोक गायन में जुटे प्रतिभाओं को न केवल एक प्लेटफॉर्म देते हैं बल्कि राज्य के लोगों को लोक परंपरा से जोड़ते हैं तिवारी की पहल पर क्षेत्र के 20 से अधिक लोक कलाकारों को मिलेगा राष्ट्रीय पहचान का प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ की लोककला और लोकसंस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की अनूठी पहल नवागढ़ में हुई। राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उपराष्ट्रपति द्वारा लक्ष्मण मस्तरिया अलंकरण से सम्मानित प्रदेश के वरिष्ठ लोक कलाकार राकेश तिवारी के लोकप्रिय पॉडकास्ट ‘गाबो बजाबो गोठियाबो की रिकॉर्डिंग 24 अक्टूबर 2026 को नवागढ़ में संपन्न हुई इस रिकॉर्डिंग ने नवागढ़-बेमेतरा अंचल के लोक कलाकारों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। एक ही मंच पर लोकगीत, लोकनृत्य, पंडवानी, नाचा और पारंपरिक वादन से जुड़े कलाकारों ने अपने कला-सफर



और अनुभवों को साझा किया। इन कलाकारों की हुई रिकॉर्डिंग- नवागढ़ के शिव खरे, पंडित चंदूलाल भास्कर, हाथाडांडु के भगवत प्रसाद निर्मलकर, नाथुराम साहू, हेमलता साहू, नूतन सिंह, भदौरा के नारायण दास कोसले व पंडित सुंदर दास कोसले, ताला के पंचम कुरें व संतोषी कुरें, मुंगेली के मनोज पटेल व जुगल किशोर साहू (मोर मयारू नाच पार्टी), कामता की पंडवानी गायिका प्रेमशिला वर्मा, डांडकापा की बिजया साहू व बिना साहू, डोमननपुर के मालिक राम लहरे, नारायण निषाद कटई, भुवन लाल

वर्मा और जेवरा-संबलपुर के कलाकार बेमेतरा के अभिभन सेन और नवागढ़ के नाथुराम साहू का विशेष सहयोग रहा। नवंबर में होगा प्रसारण। राकेश तिवारी ने बताया कि इन सभी साक्षात्कारों का प्रसारण नवंबर 2026 में उनके यूट्यूब चैनल पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य गांव-कस्बों में छिपी प्रतिभाओं का दस्तावेजीकरण और उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। सहभागी कलाकारों ने कहा कि ऐसी पहल से लोक कलाकारों को न सिर्फ मंच मिल रहा है, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध विरासत भी सुरक्षित हो रही है।

दलदलनुमा मार्गों को प्राथमिकता से किया जा रहा दुरुस्त

मंत्री रामविचार नेताम की सतत निगरानी में सड़कों का दुरुस्तीकरण तेज

बलरामपुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में सड़कों के दुरुस्तीकरण और निर्माण कार्यों में तेजी लाई जा रही है। बरसात धमने के बाद क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, गह्रों को भरने और निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने को कवायद शुरू हो गई है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम क्षेत्र में सड़क एवं अधोसंरचना विकास कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सड़कों की स्थिति को लेकर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव से विस्तृत चर्चा की है तथा उनके जिला प्रवास के दौरान भी जमीनी



हालात से अवगत कराया है। मंत्री नेताम ने कहा कि जिले की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कार्ययोजना को और प्रभावी बनाया जा रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के



विकास में सड़क संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए सड़क, पुल और पुलिया निर्माण के कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण एवं मरम्मत



कार्यों की निगरानी में जनप्रतिनिधियों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जमीनी स्तर पर सामने आने वाली कमियों को समय रहते दूर

किया जा सके। लोक निर्माण विभाग के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के बीच जिले में 358.06 करोड़ रुपये की लागत से 15 प्रमुख सड़क निर्माण एवं उन्नयन कार्य पूरे किए गए हैं। इनकी कुल लंबाई 238.63 किलोमीटर है। वर्ष 2025-26 में ही 201.37 करोड़ रुपये की लागत से 81.50 किलोमीटर सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन पूरा किया गया। इससे पहले वर्ष 2024-25 में 109.73 किलोमीटर और वर्ष 2023-24 में 47.40 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया था।

दलदलनुमा मार्गों की मरम्मत पर विशेष जोर बरसात के कारण ग्राम बरियों, बासेन, परता, भकुरा, राजपुर, झींगो, तातापानी और कमलपुर सहित कई स्थानों पर सड़कें दलदलनुमा हो गई थीं। इससे भारी ताहनों के फंसने और आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इन मार्गों का प्राथमिकता के आधार पर संभारण कराया जा रहा है, जिससे आवागमन सुगम हो सके। अंबिकापुर-रामानुजगंज-गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग-343 के पैकेज-1 के तहत राजपुरीखुर्द से पाद्री तक 49 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण एवं उन्नयन किया जा रहा है। विकासखंड राजपुर के ग्राम करजी में डामरीकरण कार्य प्रगति पर है, जबकि जलबासा, चटनिया और कुसमी में भी बिटुमिन कार्य शुरू हो चुका है। बलरामपुर से रामानुजगंज तक क्षतिग्रस्त सड़कों का चिह्नंकन कर मरम्मत कराई जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के साथ सड़क की चौड़ाई, ढलान, एलाइनमेंट और कॉम्पैक्शन की जांच की जा रही है, ताकि निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय-सीमा में पूरे हो।

नई सड़कों की पुलियाओं के कार्य भी होंगे पूरे

इसके अतिरिक्त 4.75 करोड़ रुपये की लागत से राजपुर-प्रातापुर मार्ग से कुंदी-करवा होते हुए पहाड़पारा तक चार किलोमीटर लंबी नई सड़क बनाई जाएगी। विजयनगर, भावा, चांकी, कामेश्वरनगर, मरमा और तरकाखंड में भी सीसी रोड, मुरुम रोड एवं पुलिया निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व, कृषि मंत्री रामविचार नेताम की पहल, जनप्रतिनिधियों की सहभागिता और जिला प्रशासन की सक्रियता से जिले में सड़क अधोसंरचना को मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। आगामी दिनों में मरम्मत और निर्माण कार्यों में तेजी आने से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी

दुर्ग में कानून की जानकारी से बच्चों को सुरक्षा, साहस और अधिकारों की पहचान

दुर्ग। किसी बच्चे के लिए विद्यालय केवल पढ़ाई की जगह नहीं, बल्कि सपने देखने, आगे बढ़ने और अपने भविष्य को आकार देने का स्थान होता है। लेकिन इन सपनों की राह में यदि असुरक्षा, शोषण, बाल विवाह या इंटरनेट की दुनिया में छिपे खतरे आ जाएं, तो बच्चे को केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सही जानकारी, सुरक्षा और समय पर सहायता की भी आवश्यकता होती है। इसी सोच के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग ने सुरक्षित बचपन अभियान के माध्यम से विद्यालयों में बच्चों तक कानून और उनके अधिकारों की जानकारी पहुंचाने की पहल की है।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के अध्यक्ष श्री के. विनोद कुजुर के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न विद्यालयों में जागरूकता शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्राधिकरण के सचिव श्री उमेश कुमार भागतकर के समन्वय में संचालित इन प्रयासों का केंद्रबिंदु एक सरल, लेकिन महत्वपूर्ण विचार है – बच्चे अपने अधिकारों को जानें, खतरे को पहचानें और जरूरत पड़ने पर सहायता मांगने से न डरें।



अभियान की थीम जागरूकता, सुरक्षा और संरक्षण हर बच्चे का अधिकार है, जबकि इसका मूल संदेश है – हर बच्चे का बचपन, हम सबकी जिम्मेदारी। यह संदेश केवल एक नारा नहीं, बल्कि बच्चों, परिवारों, विद्यालयों और समाज के बीच साझा जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का आह्वान है।

इसी उद्देश्य से चंद्रशेखर हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी/अंग्रेजी

माध्यम विद्यालय दीपक नगर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोसा नगर भिलाई, शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, महमारा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बिरझापुर, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चंदखुरी एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला उतई क्रमांक 2 में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में न्यायिक अधिकारियों श्री भानू प्रताप सिंह त्यागी, श्रीमती कामिनी

जायसवाल, श्रीमती ऐश्वर्या दीवान, श्रीमती प्रज्ञा अग्रवाल, श्री शाश्वत दुबे, श्रीमती अंजली सिंह, श्रीमती महिमा शर्मा, कु. आरती ध्रुव, कु. आकांक्षा सिंह, श्री राहुल सोरी, श्री पंकज शर्मा, कु. मुस्कान शर्मा ने सहभागिता की। पैलन अधिवक्ताओं, साइबर क्राइम ऑफिसर और पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने भी बच्चों तक विधिक जानकारी पहुंचाने में योगदान दिया।

कानून की जानकारी, बच्चों की अपनी

भाषा में– इस अभियान की विशेषता यह है कि बाल संरक्षण जैसे गंभीर विषयों को केवल कानूनी प्रावधानों तक सीमित न रखते हुए बच्चों के दैनिक जीवन से जोड़कर समझाने पर बल दिया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत छह विषय निर्धारित किए गए हैं – मेरा बचपन, मेरा अधिकार, कानून जानो, बचपन बनाओ, सुरक्षित क्लिक, सुरक्षित बचपन, बोलो, बताओ, बचाओ, ना बाल विवाह, ना बाल शोषण तथा जागरूक बचपन, सशक्त भारत।

इन विषयों के माध्यम से बच्चों को उनके अधिकारों, व्यक्तिगत सुरक्षा, इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग, शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया और सहायता प्राप्त करने के उपलब्ध माध्यमों से परिचित कराया जा रहा है। विद्यालयों में चरनित विषयों पर विशेष जागरूकता गतिविधियों के जरिए बच्चों को यह समझाने का प्रयास किया गया कि असुरक्षित परिस्थितियों को पहचानना, अनुचित व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाना और किसी विश्वसनीय व्यक्ति अथवा सक्षम प्राधिकारी से सहायता मांगना उनके अधिकारों का हिस्सा है।

जागरूकता से आत्मविश्वास तक– सुरक्षित बचपन की दिशा में पहला कदम यह है कि बच्चा यह समझ सके कि उसकी सुरक्षा, गरिमा और सम्मान महत्वपूर्ण हैं। उसे यह पता हो

कि किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में चुप रहना उसकी मजबूरी नहीं है और सहायता मांगने के लिए उचित व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। इसी क्रम में बच्चों को निःशुल्क विधिक सहायता तथा बाल संरक्षण से संबंधित सहायता-व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी जा रही है। अभियान का प्रथम चरण दुर्ग जिले के अधिकाधिक विद्यालयों तक पहुंचाने और बच्चों में अधिकारों के प्रति समझ विकसित करने पर केंद्रित है। बाल विवाह, बाल शोषण और ऑनलाइन जोखिमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ यह पहल बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने में समाज की सामूहिक भूमिका को भी रेखांकित करती है।

सुरक्षित बचपन अभियान का संदेश स्पष्ट है – बच्चे केवल देश का भविष्य नहीं, बल्कि वर्तमान की ऐसी जिम्मेदारी हैं, जिनकी सुरक्षा और सम्मान आज सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब बच्चे अपने अधिकारों को पहचानेंगे, अपनी बात कहने का साहस जुटाएंगे और सहायता के रास्तों से परिचित होंगे, तभी जागरूकता वास्तविक सुरक्षा में बदल सकेगी। हर बच्चे का बचपन सुरक्षित हो, हर बच्चे को आवाज सुनी जाए और हर बच्चे को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले – यही इस पहल का उद्देश्य है।

दीपावली के खरीदारी के बीच बड़ी राहत, पावर हाउस रोड पर अब नहीं लगेंगे जाम

रातोंरात बना डिवाइडर, आयुक्त की ट्रैफिक कंट्रोल प्लानिंग की हो रही तारीफ!

कोरबा। पावर हाउस रोड पर जाम का जज्बाल और त्योहारों में बढ़ते ट्रैफिक का दबाव! ऐसे में नगर निगम ने समस्या से निपटने के लिए तेजी दिखाई है। शारदा विहार मोड़ से जल संसाधन विभाग के केनाल पुल तक सड़क पर रातोंरात डिवाइडर का निर्माण कराकर निगम ने यातायात व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस पहल को लेकर नगर निगम आयुक्त की ट्रैफिक कंट्रोल प्लानिंग की चर्चा हो रही है। खास बात यह है कि व्यस्त सड़क पर दिन के समय आवागमन बाधित करने के बजाय रात में निर्माण कराया गया, ताकि आम लोगों को कम से कम परेशानी हो। पावर हाउस रोड पर दोपहर से लेकर देर रात तक वाहनों का दबाव बना रहता है। नवरात्र के



दौरान भी यहां जाम ने लोगों को परेशान किया था। अब दीपावली की खरीदारी के लिए बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। ऐसे में समय रहते यातायात व्यवस्था दुरुस्त करना जरूरी हो गया था। ट्रैफिक पुलिस ने इस समस्या को लेकर प्रस्ताव रखा, जिसके बाद नगर निगम ने तेजी से अमल करते हुए शारदा विहार मोड़ से केनाल पुल तक डिवाइडर बनवा दिया। रातोंरात हुए इस निर्माण से यह संदेश भी गया कि व्यस्त मार्ग पर

जरूरी काम कराते समय दिन के यातायात को बाधित होने से बचाने की कोशिश की जा सकती है।

जाम के झटके से मिलेगी राहत, ट्रैफिक को मिलेगी नई दिशा–इस मार्ग पर वाहनों की लगातार आवाजाही के बीच बेतरतीब मुवमेंट जाम की बड़ी वजह बनता रहा है। डिवाइडर बनने से वाहनों की व्यवस्थित दिशा में चलाने और आमने-सामने की आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे बाजार आने-जाने वाले लोगों के साथ रोजाना इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को भी राहत मिल सकती है। जाम के कारण एंबुलेंस और अन्य जरूरी सेवाओं के साथ वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका

भी बनी रहती है। ऐसे में नई व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करना महत्वपूर्ण होगा। डिवाइडर के साथ ट्रैफिक पुलिस की निगरानी और सड़क किनारे बेतरतीब पार्किंग पर नियंत्रण भी जरूरी रहेगा।

दीपावली से पहले पहल, अब असर दिखाने की बारी–पावर हाउस रोड पर जाम की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। ऐसे में त्योहार से पहले डिवाइडर निर्माण कराना नगर निगम की ओर से यातायात सुधारने की एक ठोस पहल है। ट्रैफिक पुलिस के प्रस्ताव पर तेजी से काम कराकर निगम ने नई व्यवस्था तैयार की है। अब उम्मीद है कि त्योहारों की भीड़ के बीच इस पहल का लाभ आम नागरिकों को मिल सकेगा।

रामानुजगंज के गांधी मैदान में रामलीला का शुभारंभ, जन चेतना कल्याण मंच के अध्यक्ष विकास दुबे ने किया उद्घाटन



रामानुजगंज। नगर के गांधी मैदान में रामलीला का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जन चेतना कल्याण मंच के अध्यक्ष विकास दुबे ने विधिवत पूजा-अर्चना और आरती कर भगवान को झांकी की पूजा की। इसके साथ ही रामलीला का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में भगवान की झांकी के समक्ष आरती कर श्रद्धा और भक्ति के साथ धार्मिक आयोजन की शुरुआत की गई। रामलीला के आयोजन से क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। रामलीला भारतीय संस्कृति, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के आदर्शों और धर्म की विजय का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है।

निधन : गोलकनाथ भुयन



नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी व श्री जगन्नाथ मंदिर समिति से –6 के पूर्व कोषाध्यक्ष अध्यक्ष श्री गोलकनाथ भुयन जी का आज दुःखद निधन हो गया जिनकी अंतिम यात्रा कल 28 अक्टूबर को दोपहर 12:00 बजे उनके निज निवास कुपाल नगर, शांति नगर सेंट जेवियर स्कूल के पास से रामनगर मुक्तिधाम के लिए निकलेगी वह अपने पीछे भाजपा नेता पुत्र जिंदद भुयन सहित भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं उनके निधन पर श्री जगन्नाथ समिति सेक्टर 6 एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना शोक व्यक्त किया है

भिलाई नगर। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने जनसेवा और जनहित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी शासकीय सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम करने के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को पत्र लिखा है। विधायक की इस पहल को सुरक्षा बलों के बेहतर उपयोग, जनहित के प्रति प्रतिबद्धता और सार्वजनिक जीवन में सादगीपूर्ण कार्यशैली की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक रिकेश सेन ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी की निर्भिक, कर्मठ और जनसेवा के प्रति समर्पित कार्यशैली से प्रेरित होने का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के रूप



में जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधित्व करने का दायित्व सौंपा है और जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है।

सुरक्षा कर्मियों का उपयोग कानून-व्यवस्था मजबूत करने में हो– विधायक रिकेश सेन ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि उनकी सुरक्षा में तैनात शासकीय सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम कर आवश्यकतानुसार उन्हें वापस लेकर

प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए उपयोग में लिया जाए। इस पहल का मूल उद्देश्य यही है कि शासकीय सुरक्षा व्यवस्था में उपलब्ध मानव संसाधन का उपयोग जनसुरक्षा और कानून-व्यवस्था की जरूरतों के अनुरूप किया जा सके।

प्रदेश में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका अपराध नियंत्रण, आम नागरिकों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने में है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार पुलिसकर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना जनहित की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विधायक की ओर से किया गया यह अनुरोध इसी व्यापक सोच को सामने रखता है।

जनसेवा की भावना से जुड़ी पहल– रिकेश सेन का यह कदम

इस संदेश को भी रेखांकित करता है कि जनप्रतिनिधि का पद केवल सुविधाओं और सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि जनता के प्रति जिम्मेदारी और सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग से भी जुड़ा है। यदि आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम की जाती है, तो उपलब्ध जवानों को अन्य जरूरी दायित्वों में लगाया जा सकता है।

विधायक ने अपने पत्र की प्रतिलिपि भाजपा को प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी, भाजपा छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष और पुलिस महानिरीक्षक को भी भेजी है। अब इस संबंध में शासन और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं, निर्धारित मानकों और उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर निर्णय लिया जाना है।

जनता की सुरक्षा सर्वोपरि, विधायक रिकेश ने सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम करने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

कृषक उन्नति योजना में किसान पंजीयन 31 अक्टूबर तक

बलौदाबाजार। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के मार्गदर्शन में कृषक उन्नति योजना हेतु अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से खरीफ मौसम में धान के स्थान पर अन्य फसल जैसे दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल व कपास फसल के लिए पंजीयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत किसान पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 तक निर्धारित है। जिले का अधिकांश क्षेत्र वर्षा आधारित होने से मौसमी प्रतिकूलता व कृषि आदान लागत में वृद्धि के कारण कृषि आय में अनिश्चितता बनी रहती है, फलस्वरूप कृषक फसल उत्पादन के लिए आवश्यक आदान जैसे उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, यांत्रिकीकरण एवं नवीन कृषि तकनीकी में पर्याप्त निवेश नहीं कर पाते। राज्य सरकार द्वारा कृषि में पर्याप्त निवेश एवं कास्ट लागत में राहत देने के लिए कृषक उन्नति योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही फसल विविधिकरण को प्रोत्साहन देने, दलहन तिलहन

फसलों के क्षेत्र विस्तार तथा इनके उत्पादन में आय निर्भरता के लक्ष्य के साथ इस योजना के तहत चिन्हित अन्य फसलों पर भी आदान सहायता राशि दिये जाने का निर्णय लिया गया है। कृषक उन्नति योजना का लाभ केवल उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिन्होंने एकीकृत किसानों पोर्टल एवं एग्री स्ट्रेट पोर्टल में पंजीयन अतिवर्त्य रूप से कराया हो। विगत खरीफ मौसम में एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीकृत ऐसे कृषक जिन्होंने धान फसल लगाये हो तथा व गिरदावरी पूर्ण हो। जिनके द्वारा खरीफ मौसम में दलहन, तिलहन, मक्का लघु धान्य फसल (कोदो, कुटकी एवं घान्घी) व कपास फसल के लिए पंजीयन कराया गया हो। योजना के दिशा-निर्देशानुसार विधिक व्यक्तियों तथा ट्रस्ट, मॉडल, प्राइवेट लिमि, कम्पनी, शाला विकास समिति, केन्द्र एवं राज्य शासन के संस्थान, महाविद्यालय आदि संस्थाओं को योजना से लाभ लेने की पात्रता नहीं होगी।

कमिश्नर बिलासपुर द्वारा कलेक्टर को जांच के आदेश दिए जाने के डेढ़ माह बाद भी जांच नहीं होने पर

कलेक्टर के बाद अब सचिव पंचायत ने अनियमितता की जांच का जिम्मा जिला पंचायत सीईओ को सौंपा

कोरबा। आकांक्षी जिला कोरबा में ‘रीपा’ (ग्रामीण औद्योगिक पार्क) के संरचना (गोदाम) निर्माण में अनियमितता एवं औद्योगिक इकाई स्थापित करने शासन के नियमों के विपरीत स्व सहायता समूहों को गुमराह कर फर्मों रामसा प्रा.लि. एलॉयड रायपुर (छ.ग.) एवं ब्रिटिश इंडिया कंपनी कोरबा के माध्यम से आपूर्ति किए गए करोड़ों रूपए के मशीनी सामग्रियों की भौतिक स्थापना, गुणवत्ता, क्रय, भुगतान प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए जाने के डेढ़ माह बाद भी जांच नहीं होने पर अब सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला – पंचायत कोरबा को जांच का आदेश दिया है। यहाँ बताना होगा कि मुख्य सचिव छ्पा शासन को 24 जनवरी 2024 को आकांक्षी जिला कोरबा में ‘रीपा’ (ग्रामीण औद्योगिक पार्क) मे हुई



जिम्मेदारों का चिन्हांकन कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने संबंधी शिकायत में सुशासन का दावा करने वाली साय सरकार दस्तावेजी शिकायत के उपरंत भी जांच पर जांच आदेश निकाल कागजी औपचारिकता का निर्वहन

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला – पंचायत कोरबा को जांच का आदेश दिया है। यहाँ बताना होगा कि मुख्य सचिव छ्पा शासन को 24 जनवरी 2024 को आकांक्षी जिला कोरबा में ‘रीपा’ (ग्रामीण औद्योगिक पार्क) मे हुई

अनियमितता के मामले में व्यापक लोकहित में राज्य स्तरीय टीम गठित कर 30 दिवस के भीतर प्रकरण की जांच का अनुरोध किया गया था। पत्र के माध्यम से आकांक्षी जिला कोरबा में ‘रीपा’ (ग्रामीण औद्योगिक पार्क) के संरचना (गोदाम) निर्माण में अनियमितता एवं औद्योगिक इकाई स्थापित करने शासन के नियमों के विपरीत स्व सहायता समूहों को गुमराह कर फर्मों रामसा प्रा.लि. एलॉयड रायपुर (छ.ग.) एवं ब्रिटिश इंडिया कंपनी कोरबा के माध्यम से आपूर्ति किए गए

करोड़ों रूपए के मशीनी सामग्रियों की भौतिक स्थापना, गुणवत्ता, क्रय, भुगतान प्रक्रिया की व्यापक लोकहित में राज्य स्तरीय टीम से जाँच कराकर जिम्मेदारों का चिन्हांकन कर आवश्यक कार्यवाही किए जाने का अनुरोध किया गया था, जिसमें कांग्रेस शासनकाल में स्वीकृत ‘रीपा’ योजना में हुई तमाम अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए फर्म के शेष भुगतान पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य स्तरीय टीम से प्रकरण की व्यापक लोकहित में जांच कराकर

जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारियों का चिन्हांकन कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया गया था।

करीब डेढ़ साल बाद साय सरकार को प्रकरण में जांच की सुघ आई। शिकायतकर्ता को 07.08.2026 को प्रातः 12:00 बजे कार्यालय उपसंचालक, जिला पंचायत कोरबा में उक्त शिकायत के संबंध में आवश्यक साक्ष्य दस्तावेज सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करने का लेख था। जबकि प्रेषित शिकायत पत्र में प्रकरण की राज्य

स्तरीय टीम से जांच का अनुरोध किया गया था जिसे न केवल जिला स्तर पर दिया गया वरन् प्रकरण में निचले स्तर के अधिकारी जो प्रकरण की जांच हेतु सक्षम नहीं हैं उन्हें जांच का जिम्मा सौंपकर जांच प्रक्रिया के नाम पर औपचारिकता का निर्वहन किया जा रहा था। प्रेषित शिकायत पत्र में तत्कालीन जिला पंचायत सी.ई.ओ. (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) नूतन कंव्वर एन.आर.एल.एम. के जिम्मेदार अफसरों के भूमिका पर सवाल उठाए गए थे, निष्पक्ष जांच

का अनुरोध किया गया था। इसके बावजूद जिला पंचायत सी.ई.ओ. के अधीनस्थ अधिकारी उपसंचालक पंचायत– कोरबा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो कि शासन के निर्धारित नियमों के सर्वथा विपरीत था। एक कनिष्ठ अधिकारी अपने से वरिष्ठ अधिकारी के संदर्भ में प्राप्त शिकायती प्रकरणों की जांच नहीं कर सकते। पुरे प्रकरण में जिला पंचायत व एन.आर.एल.एम. शाखा के जिम्मेदार अधिकारी / कर्मचारियों की संलिप्तता परिलक्षित हो रही थी।